 RNI No. RAJHIN/2020/11458

वर्षः 5 अंकः1 15 जनवरी, 2025 मूल्यः 60 रु.

राजस्थान टुडे

आप-दा बनाम अंगद का पांव

पेज 9-10

महाकुंभ से तय होगा राजनीति का नया सूर्य...

पेज 7-8

अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीं आसमां बाकी है

पेज 13-16

GRACEFUL ELEGANCE: THE ESSENCE OF WOMEN'S ETHNIC WEAR

bandhani
The Ethnic Store

When it comes to fashion that celebrates tradition, elegance, and individuality, nothing compares to women's ethnic wear. A perfect blend of heritage and modernity, ethnic clothing captures the heart of cultural diversity while embracing contemporary trends.

Whether it's a festive occasion, a wedding celebration, or simply a desire to feel connected to your roots, ethnic wear offers a stunning range of styles to suit every mood and moment.

Bandhani The Ethnic Store offers a broad range of women's wear. Bandhani's journey began in Nai Sarak, Jodhpur, in 2019 with Rajasthan's largest ethnic wear store.

Thanks to the love and support we received, we expanded to Sardarpura in 2022, offering an even wider range of ethnic styles. In 2023, we spread the charm to Ahmedabad, making our vibrant collections a favourite among ethnic wear lovers. And in 2024, Jaljog's bridal store became the go-to destination for its stunning range of timeless bridal wear.

This provides a wide range of:- Kurti Set, Dress Material, Single kurtis, Co-ord Set, Semi-Party Wear, One-Piece, Anarkali, Lehenga, Indo-Western, Sharara, Garara, etc.

राजस्थान टुडे

www.rajasthantoday.online

RNI No. RAJHIN/2020/11458

वर्ष 5, अंक 1, 15 जनवरी, 2025

प्रत्येक माह 15 तारीख को प्रकाशित

प्रधान सम्पादक
दिनेश रामावत

संपादकीय कार्यालय
बी-4, फोर्थ फ्लोर, एम.आर. हाईट्स
महावीर कॉलोनी, भास्कर सर्किल,
रातानाड़ा, जोधपुर - 342011
व्हाट्सएप नंबर - 9828032424
ई-मेल - rajasthantoday@gmail.com

सभी विवादों का निपटारा जोधपुर की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में किया जाएगा।

राजस्थान टुडे में प्रकाशित आलेख लेखकों की राय है। इसे राजस्थान टुडे की राय नहीं समझा जाए। राजस्थान टुडे के मुद्रक, प्रकाशक और सम्पादक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। हमारी भावना किसी वर्ग या व्यक्ति को आहत करना नहीं है। विज्ञापनदाताओं के किसी भी दावे का उत्तरदायित्व राजस्थान टुडे का नहीं होगा।

• मारवाड़ मीडिया प्लस के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक पूनम अस्थाना द्वारा बी-4, फोर्थ फ्लोर, महावीर कॉलोनी, रातानाड़ा, जोधपुर-342011 से प्रकाशित और डी.बी. कॉर्प लिमिटेड, 01 पार्श्वनाथ इंडस्ट्रीयल एरिया, रिलायंस वेयर हाउस के पास, मोगरा कलां, जोधपुर-342802 में मुद्रित।

सुर्खियां

महाकुंभ 7

महाकुंभ से तय होगा राजनीति का नया सूर्य...

दिल्ली चुनाव 9

आप-दा बनाम अंगद का पांव

आवरण कथा 13

अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीं... आसमां बाकी है

सामयिक 21

भाजपा की सत्ता में ही बनेगी बात

12. राजकाजः संघर्ष, संतुलन और सियासत

17. सियासतः जल्दबाजी का फैसला या चुनावी रणनीति?

प्रदेश गौरव

पेज 26

मारवाड़ की कला, साहित्य, संस्कृति व विरासत के संरक्षक

30. खेल-खिलाड़ीः जोधपुर पोलो का 147 वर्ष का स्वर्णिम इतिहास

39. प्रतिबिंबः राजनीति के क्षितिज पर पश्चिम से उदय हुआ रवि

एक देश-एक चुनाव : प्रगतिशील कदम

एक देश एक चुनाव' पर बनी उच्च स्तरीय कमिटी की सिफारिशों को केन्द्रीय केबिनेट की मंजूरी के बाद अब यह मामला संयुक्त संसदीय समिति के पास विचाराधीन है। मोदी सरकार की इच्छा अगले पांच वर्षों में इसे सारे देश में लागू करने की है। यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्र की महती आवश्यकता है। यह बात कानून एवं कार्मिक मामलों की स्थायी संसदीय समिति की रिपोर्ट में भी उजागर हुई है। इस पर नीति आयोग, विधि आयोग व चुनाव आयोग की पहल भी होती रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से लेकर प्रधानमंत्री के अनेक वक्तव्यों में भी यह मुद्दा चर्चा के केंद्र में रहा है।

किसी भी जीवंत लोकतंत्र में चुनाव एक आवश्यक प्रक्रिया है। भारत जैसे विशाल देश में अबाध चुनावी प्रक्रिया सम्पन्न कराना हमेशा से एक टेढ़ी खीर रहा है। लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव का कोई नियत समय नहीं होता है। यह सांसदों और विधायकों के विश्वास मत और सरकार की मंशा के अधीन होता है। इसके अलावा पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव को भी यदि इसमें शामिल कर लिया जाए तो ऐसा लगता है जैसे देश एक चुनावी दुश्चक्र में फंस गया हो। इससे न केवल प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं, बल्कि राष्ट्रीय संपत्ति और जनता के पैसों का भी नुकसान होता है। इसलिए नीति निर्धारकों का यह विचार उचित है कि क्यों न लोकसभा, विधान सभाओं और पंचायत व नगरपालिकाओं के चुनाव साथ-साथ करवाएं जाएँ। इस प्रकार 'एक देश एक चुनाव' लोकसभा और विधानसभाओं तथा स्थानीय निकायों के चुनावों को साथ-साथ करवाये जाने का वैचारिक उपक्रम है। इस संदर्भ में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश है कि चुनाव दो चरणों में कराए जाएं। पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव कराएं जाएं तथा दूसरे चरण में नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनाव हों। इन्हें पहले चरण के चुनावों के साथ इस तरह से कॉर्डिनेट किया जाए कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के सौ दिनों के भीतर इन्हें पूरा किया जाए। इसके लिए कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल में कटौती करनी होगी और कुछ के कार्यकाल में विस्तार करना होगा। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर इस उच्च स्तरीय समिति ने कुल 47 राजनैतिक दलों से बातचीत की। इसमें कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों समेत केवल 15 दलों ने विरोध जताया जबकि 32 दलों ने इस पर अपनी सहमति प्रदान की। लेकिन सवाल उठता है कि यह एक देश एक चुनाव इतना आवश्यक क्यों है?

चुनावों की बारंबारता के कारण बार-बार आदर्श आचार सहिंता यानी मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट लगाना पड़ता है। इससे सरकार आवश्यक नीतिगत निर्णय नहीं ले पाती है और विभिन्न योजनाओं-परियोजनाओं की गतिविधियाँ प्रभावित होती है। यदि देश में एक ही बार लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव संपादित किये जाएँ तो अधिकतम तीन महीने ही आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी, बांकी के चार साल नौ महीनें तो निर्बाध रूप से विकासात्मक परियोजनाओं को संचालित किया जा सकता है।

एक देश एक चुनाव के पक्ष में दूसरा तर्क यह है कि इससे चुनावों पर होने वाले भारी खर्च में कमी आएगी और राष्ट्रीय कोष में वृद्धि होगी। दिनों-दिन चुनावी व्यय में होने वाली वृद्धि इस बात का सबूत है कि चुनावों में बढ़ता बेतहाशा खर्च देश की आर्थिक सेहत के लिए नुकसानदेह है। एक आकलन के मुताबिक पांच सालों में देश में होने वाले समस्त चुनावों यथा लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनावों का कुल खर्चा यदि जोड़ा जाए तो यह लगभग ढाई से तीन लाख करोड़ रूपये होगा।

एक देश एक चुनाव के पक्ष में दूसरा तर्क यह है कि इससे चुनावों पर होने वाले भारी खर्च में कमी आएगी और राष्ट्रीय कोष में वृद्धि होगी। दिनों-दिन चुनावी व्यय में होने वाली वृद्धि इस बात का सबूत है कि चुनावों में बढ़ता बेतहाशा खर्च देश की आर्थिक सेहत के लिए नुकसानदेह है।

तीसरी बात यह कि एकसाथ लोकसभा और विधान सभाओं के चुनाव होने से काले धन पर रोक लगेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम कसने में भी मदद मिलेगी। यह चुनाव सुधार की दिशा में भी कारगर कदम सिद्ध होगा। चौथी बात यह कि वन नेशन वन इलेक्शन से कर्मचारियों के मूल कृत्यों के निर्वहन में तीव्रता आएगी साथ ही लोगों के सार्वजनिक जीवन के व्यवधान में भी कमी आएगी।

पांचवीं बात यह है कि छोटे राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों को भी बार-बार चुनावी प्रचार और संसाधन की कमी जैसी चुनौती से निपटने में आसानी होगी और वो पूरी ताकत से जनता के मुद्दे को पटल पर लाने में सक्षम साबित होंगे। चुनावों की अधिकता वोटरों में अरुचि पैदा करती है और इससे मतदान प्रतिशत में कमी आने का खतरा बढ़ता है। जबकि पांच वर्ष में एकसाथ एकबार चुनाव होने से आम मतदाता में चुनावों के प्रति दिलचस्पी बढ़ेगी तथा वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

छठी और अंतिम बात यह है कि एक देश एक चुनाव कोई अनूठा प्रयोग नहीं है कि इसका विरोध किया जाए, बल्कि इस प्रकार की प्रथा शुरूआती चार चुनावों में अपनाई जाती रही है। इसलिए जो भी दल इसकी व्यावहारिकता को लेकर संशय या विरोध जताते हैं उन्हें सन 1952, 1957, 1962 और 1967 के आम चुनावों को जरुर याद करना चाहिए, जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ-साथ करवाए गए थे। हाल ही में जब अठारहवीं लोकसभा चुनावों के साथ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल के विधानसभा चुनाव हुए हैं तो फिर बाकी राज्यों के क्यों नहीं हो सकते?

आगे की राह इसमें दो राय नहीं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, चुनावी चक्रव्यूह में घिरा हुआ नजर आता है। इसलिए चुनावों के चक्रव्यूह से देश को निकालने के लिए एक विषद चुनाव सुधार अभियान की आवश्यकता है। इसमे जनप्रतिनिधित्व की धारा को अपटूडेट बनाना, काले धन पर रोक लगाना, राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ सख्त कानून बनाना, रचनात्मक अविश्वास व् रचनात्मक विपक्ष की परिपाटी को बढ़ावा देना तथा जनशिक्षण के द्वारा लोगों में राजनीतिक चेतना व जागरूकता का सही विकास करना जैसे जरूरी कदम उठाने होंगे। सोचने की बात है कि जब वन नेशन वन टैक्स का विचार फलीभूत हो सकता है तो वन नेशन वन इलेक्शन को आजमाने में क्या परेशानी है? ऐसे भी एकसाथ चुनाव करवाने वाला भारत कोई एकलौता देश नहीं होगा बल्कि बेल्जियम, स्वीडेन, दक्षिण अफ्रीका भी एक साथ चुनाव करवाते आए हैं। इस दिशा में राजनीतिक दलों को भी खुले मन से चुनाव सुधार की दिशा में अग्रसर होने की आवश्यकता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि हम राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुकूल राजनीतिक प्रणाली को नहीं सुधारेंगे तो यह राष्ट्र को दीमक की तरह चट कर सकती है। अतः एक देश एक चुनाव एक प्रगतिशील कदम है जो कि राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुकूल है।

महाकुंभ नहीं देखा ... तो क्या देखा

राधा रमण
वरिष्ठ पत्रकार प्रयागराज से

उत्तरप्रदेश के प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समागम 'महाकुंभ 2025' शुरू हो चुका है। देशभर के संतों-महंतों और धर्माचार्यों ने पखवाड़ेभर पहले से कुंभ नगरी में डेरा जमा लिया है। मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। ऐसा आखिर हो भी क्यों न, मोक्ष की कामना भला किसे नहीं रहती ? अथर्ववेद की टीका में लिखा है कि कुंभ का अर्थ समय का इष्टकाल होता है जो जीवों को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाता है।

उत्तरप्रदेश सरकार ने महाकुंभ की तैयारियों के लिए 5060 करोड़ का बजट बनाया है। इसमें कितना खर्च होता है यह तो आयोजन के बाद पता चलेगा। इस बार उत्तरप्रदेश सरकार की अपील पर केंद्र ने भी दिल खोलकर खजाना खोला है। केंद्र ने इसके आयोजन के लिए 2100 करोड़ रुपये दिया है।

यह पिछले महाकुंभ से करीब चार गुना ज्यादा है। पिछलीबार सरकार ने 1214 करोड़ रुपये आवंटित किया गया था जिसमें 1017 करोड़ रुपये ही खर्च हो सके थे। हालाँकि उत्तरप्रदेश सरकार ने इस बार महाकुंभ से 2 लाख करोड़ रुपये कमाने का लक्ष्य भी रखा है। राज्य सरकार ने महाकुंभ के दौरान 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुँचने की संभावना जताई है।

सरकार की ओर से महाकुंभ की तैयारियों के तहत कुल 421 परियोजनाओं पर काम किया गया। इनमें सड़क, आवास, परिवहन, पुल-पुलिया और सुरक्षा शामिल है। राज्य सरकार के लोक निर्माण, आवास और नियोजन, सेतु निगम, जल संसाधन, पर्यटन, सिंचाई और नगर निगम पिछले एक साल से आयोजन की तैयारियों में जी-जान से जुटे रहे हैं। राज्य सरकार का कोई न कोई मंत्री हर रोज प्रयागराज में कैम्प किये रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आयोजन की तैयारियों की निगरानी करते रहे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 'महाकुंभ भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का परिचायक है। जो कि भारत समेत पूरी दुनिया को अपनी परंपराओं पर गर्व करने का अवसर प्रदान करता है। इस बार का महाकुंभ भव्य, दिव्य और डिजिटल होगा। मेला परिसर में डेढ़ लाख से अधिक शौचालय बनाए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं हो। रेलवे ने कई मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं ताकि यात्रियों को आने-जाने में कठिनाई न हो। रेलवे स्टेशन से मेला तक लोकल परिवहन की पुख्ता व्यवस्था की गई है। एक जनवरी से मेला अवधि तक प्रयागराज स्थित बमरौली हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है, ताकि दुनियाभर से श्रद्धालु महाकुंभ में आ-जा सकें। मेला परिसर के साथ-साथ पूरे प्रयागराज में चप्पे-चप्पे पर चौकसी बरती जा रही है। सादी वर्दी में पुलिस और सुरक्षाबलों के जवान तैनात किये गए हैं। इसके अलावा ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। मेला परिसर और शहरभर में रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। होटलों, धर्मशालाओं और अतिथि गृहों को सजाया-संवारा गया है। मेला परिसर में बहुतायत की संख्या में खोया-पाया केंद्र बनाए गए हैं। संगम तट पर स्नान करने और कपड़े बदलने के लिए काफी संख्या में चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है। हजारों की संख्या में नावों और गोताखोरों को तैनात किया गया है। मेले की कवरेज के लिए मीडिया सेंटर और अलग-अलग मीडिया समूहों के लिए टेंट के आवास की व्यवस्था की गई है। संगम के उस पार कई एकड़ में संतों-महंतों के पंडाल लगाए गए हैं। पूरा वातावरण आध्यात्मिक नजर आता है। कथा-प्रवचन के दौर चल रहे हैं।

ऋग्वेद और अथर्ववेद में कुंभ शब्द का तो उल्लेख ...लेकिन मेले जैसी कोई बात नहीं

सवाल उठता है कि आखिर महाकुंभ क्यों, कब से और कब-कब मनाया जाता है ? शास्त्रों में इस संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। ऋग्वेद और अथर्ववेद में कुंभ शब्द का तो उल्लेख है लेकिन मेले जैसी कोई बात नहीं है। अपना देश शुरू से ही धर्मभीरु रहा है। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान मिले अमृत कलश को जब दानवों ने देवताओं को पराजित कर हासिल कर लिया तो लुटे-पिटे देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। भगवान विष्णु ने देवताओं से किसी प्रकार अमृत कलश हासिल करने को कहा। फिर योजना बनी कि दानवों से अमृत कलश चुराई जाए। तब इंद्र के पुत्र जयंत को यह जिम्मेदारी दी गई। जयंत की मदद के लिए देवताओं ने चन्द्रमा, सूर्य, बृहस्पति और शनि को सहयोग करने को कहा। बाद में जयंत ने अमृत कलश दानवों के चंगुल से चुरा लिया और स्वर्ग ले गए। कहा जाता है कि अमृत कलश स्वर्ग ले जाने के क्रम में उसकी बूँदें चार स्थानों पर छलक कर गिर गईं। वह चार स्थान थे हरिद्वार, प्रयागराज, नाशिक और उज्जैन। चूंकि इस पूरी प्रक्रिया में 12 दिन लगे थे और मनुष्यों के एक वर्ष के बराबर देवताओं का एक दिन होता है। इसलिए हर 12 वर्ष के बाद इन चारों स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। इसी प्रकार चूंकि छह दिन के प्रयास के बाद अमृत कलश देवताओं को हासिल हो गया था, इसीलिए हर छह वर्षों के बाद अर्द्धकुंभ आयोजित होता है। मान्यता यह भी है कि इन ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही कुंभ अथवा महाकुंभ कहाँ आयोजित किया जाए, तय होता है।

कुंभ अथवा महाकुंभ कब कहाँ आयोजित होता है

हरिद्वार – चैत्र माह में जब बृहस्पति, शनि की कुंभ राशि में विराजमान हों और सूर्य मेष राशि में निवास करते हों तो हरिद्वार में महाकुंभ अथवा कुंभ का आयोजन होता है।
प्रयागराज – माघ माह में जब बृहस्पति, वृषभ या मेष राशि में हों और सूर्य तथा चन्द्रमा दोनों शनि की मेष राशि में हो तो प्रयागराज में महाकुंभ अथवा कुंभ का आयोजन किया जाता है।
नाशिक – भाद्र माह में जब सूर्य और बृहस्पति दोनों सूर्य की सिंह राशि में हों अथवा चन्द्रमा, सूर्य और बृहस्पति तीनों अमावस्या के दिन कर्क राशि में हों तो नाशिक में महाकुंभ अथवा कुंभ का आयोजन होता है।
उज्जैन – चौथा महाकुंभ अथवा कुंभ का आयोजन उज्जैन में होता है। यह आयोजन तब होता है जब चैत्र माह में बृहस्पति सिंह राशि में हों और सूर्य मेष राशि में हों।
इसी प्रकार बारी-बारी से चारों स्थानों पर महाकुंभ अथवा कुंभ का आयोजन किया जाता है। मान्यता यह भी है कि इन आयोजनों में शामिल होने, नित्य स्नान के बाद भोजन प्रसाद ग्रहण करने और कल्पवास करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है।

महाकुंभ 2025 के मुख्य स्नान

महाकुंभ के आयोजकों, अखाड़ा परिषद् ने प्रयागराज में 13 जनवरी से चल रहे महाकुंभ में कुल छह मुख्य स्नान बताये हैं। इनमें तीन शाही स्नान घोषित किये गए हैं। वह हैं – 14 जनवरी, मकर संक्रान्ति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या और 3 फरवरी वसंत पंचमी। शाही स्नान में नागा साधुओं के अलावा अलग-अलग अखाड़ों के संत-महंत गाजे-बाजे और नृत्य करते प्रसन्न मुद्रा में पहले स्नान करते हैं। फिर आम आदमी को स्नान करने का मौक़ा मिलता है। हमने देखा कि 14 जनवरी शाही स्नान में संतों- महंतों के अलावा करोड़ों लोगों के जनसैलाब ने कैसे उत्साहपूर्वक संगम में स्नान किया। इस दौरान संगम नगरी की फिजां देखते ही बनती थी। जिन्होंने मकर संक्रान्ति पर संगम में डुबकी लगाई वह तो पुण्य के भागी बने ही, जिन्होंने टेलीविजन पर यह दृश्य देखा वह भी धन्य हो गए, उनकी आँखें निहाल हो गईं।

शाही स्नान के अलावा 4 फरवरी को अचला सप्तमी, 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि को भी मुख्य स्नान है। बताने की जरूरत नहीं है कि शाही और मुख्य स्नान के दिन महाकुंभ में भारी भीड़ जुटती है। महाकुंभ के दौरान किसी भी दिन संगम में डुबकी लगाने का वही महत्त्व होता है जो मुख्य स्नान का होता है। तो देर किस बात की, आप भी जाइए और अपने परिजनों को भी लेकर जाइए महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए। कुछ वर्षों पहले उत्तरप्रदेश सरकार ने नारा दिया था कि 'यूपी नहीं देखा तो क्या देखा', हम तो यही कहेंगे कि महाकुंभ नहीं देखा तो क्या देखा !

महाकुंभ से तय होगा राजनीति का नया सूर्य...

2013 में प्रयागराज में ही मोदी के चेहरे पर मोहर लगी थी अब महाकुंभ में राजनीतिक मंथन में संघ और संत समाज धर्म संसद में मोदी के विकल्प के नाम पर करेगा मंथन

योगी बनेंगे चेहरा

पंकज मुकाति
वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक

महाकुंभ का प्रयागराज में आगाज़ हो गया है। 2013 में इसी जगह से कुम्भ में प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगी थी। इस बार फिर कुंभ है संघ और सनातनी समुदाय एक बार फिर प्रधानमंत्री के लिए मोदी के बाद कौन पर मंथन कर रहा है। दोनों कुम्भ के बीच बदला है तो सिर्फ एक बात इलाहबाद का नाम प्रयागराज हुआ और कुम्भ इस बार महाकुम्भ के रूप में है। 144 साल बाद बने इस योग को वो योग बताया जा रहा है जिसमे समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई थी। इस भारतीय राजनीति के समुद्र में से एक नया मोती सनातनी मोती निकालने का मंथन होगा। संघ और संतों की निगाह में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोदी का सबसे बेहतर विकल्प हो सकते है। महाकुंभ के लिए योगी की महा तैयारियों से भी इसकी झलक देखने को मिल रही है।

2013 के कुंभ में भाजपा के प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगी थी। नरेंद्र मोदी सौ फीसदी उम्मीदों पर खरे उतरे। वे आज भी सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। उनका जादू तीसरे कार्यकाल के बावजूद बरक़रार है। पर 74 की उम्र पार कर चुके मोदी के विकल्प की तलाश शुरू हो गई है। सबसे कठिन है मोदी जैसा करिश्माई नेता तलाशना। सारी निगाहें इस मंथन में बार बार भगवाधारी योगी आदित्यनाथ पर ही ठहर रही है। हालाँकि अभी चुनाव में बहुत वक्त है फिर भी संघ मंथन और माहौल बहुत पहले से बनाना शुरू कर देता है। ये संघ को करीब से जानने वाले बेहतर ढंग से जानते हैं। संघ अचानक वाला कोई काम करता ही नहीं।

तमाम मीडिया रिपोर्ट्स भी इस और इशारा करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रांत स्तर के एक पदाधिकारी ने कुछ दिन पहले स्पष्ट तौर पर कहा था कि प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेंभाजपा के अगले प्रधानमंत्री के चेहरे के नाम का प्रस्ताव आ सकता है। योगी आदित्यनाथ के नाम पर सभी की रजामंदी है। अभी लोकसभा चुनाव दूर हैं, इसलिए सीधे तौर पर उनके नाम का ऐलान नहीं होगा। पर माहौल यही से बनेगा या बनना शुरू हो जाएगा।

12 साल पहले प्रयागराज में ही संघ ने नरेंद्र मोदी का नाम संतों के सामने रखा... इस बार

बारह साल पहले प्रयागराज में ही संघ ने नरेंद्र मोदी का नाम संतों के सामने रखा था। उनके समर्थन के बाद नरेंद्र मोदी को भाजपा का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया गया। संघ और उसके तमाम संगठन इस बात के संकेत दे रहे हैं कि योगी के नाम पर सहमति है। लोकसभा चुनाव हों या विधानसभा चुनाव, योगी आदित्यनाथ का नाम स्टार प्रचारकों की में शामिल है। वे राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड से लेकर साउथ में तमिलनाडु व तेलंगाना तक चुनावी रैलियां कर चुके हैं। एक तरह से वे पूरे भारत का जाना पहचाना चेहरा बन चुके है या पार्टी ने पूरे सुनियोजित तरीके से योगी को हिंदुस्तान का चेहरा बना दिया है। याद होगा कि 2010 से ही मोदी के नाम पर पूरे देश में प्रचार होना शुरू हो गया था। संघ ने रणनीति के साथ ऐसा माहौल बनाया था कि मोदी पूरे भारत व हिंदुत्व का चेहरा बन चुके थी। उनके नाम की घोषणा का पूरे देश ने स्वागत किया था।

> मोदी भी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आज योगी उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री है। उत्तरप्रदेश देश में सरकार बनवाने वाला राज्य है। अयोध्या का मंदिर भी यही हैं और मथुरा, काशी भी राज्य में हैं। खुद मोदी ने अपना लोकसभा चुनाव इसी राज्य में आकर लड़ा था। वे गुजरात से यही उत्तरप्रदेश के वाराणसी से चुनाव लड़े। ऐसे में योगी तो उत्तरप्रदेश से ही हैं उनकी सम्भावना और मजबूत होती है।

नवंबर में हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के 'बंटेंगे तो कटेंगे' नारे का असर भी दिखा। यहां उन्होंने 11 रैलियां कर 17 कैंडिडेट के लिए वोट मांगे थे। इनमें 15 चुनाव जीत गए। योगी आदित्यनाथ ने ये नारा यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के दौरान बार-बार दोहराया। इसके बाद यही नारा महाराष्ट्र में इस्तेमाल हुआ। PM मोदी ने 5 अक्टूबर को ठाणे और वाशिम में हुई रैलियों में अलग ढंग से यही बात कही।

संघ के एक वर्ग का मानना है कि 'बंटेंगे तो कटेंगे' का नारा भले योगी आदित्यनाथ के मुंह से निकला हो, लेकिन इसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। ये संघ की शाखाओं में गाया जाने वाला बहुत पुराना गीत है। इसे आजादी के समय से गाया जाता है। ये गीत था-

'इतिहास कहता है कि हिंदू भाव को जब-जब भूले, आई विपदा महान, भाई छूटे, धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान'

संघ की रणनीति बहुत स्पष्ट है कुंभ में इस बार हिंदू एकता की चर्चा होगी । बंटेंगे तो कटेंगे योगी से बुलवाने का मकसद ही उनको स्थापित करना था। अब हिन्दू एकता और खांटी हिंदूवादी चेहरे का माहौल बन गया है। निश्चित ही योगी के नाम पर मोदी के नाम जैसे मुहर इस वक्त नहीं लगेगी क्योंकि 'तब कुंभ के अगले साल लोकसभा चुनाव थे। इसलिए मोदी के चेहरे पर पक्की मुहर के लिए उस आयोजन से बेहतर कोई और वक्त नहीं हो सकता था।' 'इतने बड़े स्तर पर हिंदू समाज के संगठन और साधु-संतों का जमावड़ा फिर कहां मिलता। इस बार कुंभ और चुनाव के बीच 4 साल का फासला है। नाम पर तो चर्चा होगी, लेकिन सभी संगठनों के बीच एक प्रस्ताव की तरह इसे लाया जाएगा।'

> *संघ की सूची में सिर्फ एक और एक ही नाम है योगी आदित्यनाथ। प्रयागराज हिन्दू संगठन से जुड़े नेता योगी आदित्यनाथ का नाम और भी मजबूती से लेते हैं। वे कहते हैं, संघ किसी को ऐसे ही आगे नहीं लाता। उसके लिए जमीन तैयार होती है। जमीन पर खाद-पानी दिया जाता है। पहले छोटा सा अंकुर फूटता है और फिर पौधा। यही काम करने का तरीका है। योगी ही वो नाम है इसके लिए पिछले एक साल से राजनीतिक घटनाक्रम और कुंभ को मिल रहे आशीर्वाद से समझना होगा।*

अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और कुंभ मेले के आयोजकों में शामिल रविंद्र पुरी ने मीडिया से कहा योगी जी हिंदू धर्म और सनातन के सबसे मजबूत स्तंभ हैं। वे कतार में हैं। उनकी दावेदारी मजबूत है। कतार में तो अमित शाह का नाम भी है, लेकिन अभी मोदी जी बहुत सक्रिय हैं। किसी प्रधानमंत्री के पद पर रहते दूसरे उम्मीदवार की चर्चा ठीक नहीं। फिर भी हम भविष्य पर चर्चा करेंगे बस अंतर ये होगा कि 2013 की तरह मोदी-मोदी जैसे नारे नहीं लगेंगे। अभी बहुत वक्त है।

कुंभ में ऐसे आया था मोदी के नाम का प्रस्ताव

'2012 से ही नरेंद्र मोदी के नाम पर अशोक सिंघल संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुहर लगवाना चाहते थे। मोहन भागवत उनके नाम पर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे।' बहुत कोशिशों के बाद अशोक सिंघल ने मोहन भागवत को नरेंद्र मोदी के नाम पर राजी कर लिया। उसके बाद कुंभ में धर्म संसद हुई। उसमें मोहन भागवत ने हिंदू और संत समाज के बीच पहली बार नरेंद्र मोदी का नाम लिया था। 'धर्म संसद का आखिरी दिन था। तारीख 5 फरवरी, 2013 थी। करीब 10 हजार दंडी स्वामी मौजूद थे। सभी ने चिमटा बजाकर मोदी का नाम लिया। उनके नाम के नारे लगाए। कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। फिर यही नारे जनता के बीच भी लगे। ये जनता संतों की भक्त थी।

मोदी के नाम को आगे लाने का पूरा श्रेय अशोक सिंघल को ही जाता है। तोगड़िया जी इस विचार से पूरी तरह सहमत नहीं थे। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कभी असहमति नही जताई। धीरे-धीरे वे संगठन के कामों से दूर हो गए और अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद नाम का नया संगठन बनाया। सिंघल जी और तोगड़िया जी के बीच वैसे भी कुछ बातों और विचारों पर भिन्नता थी। सिंघल जी ने भी इसे कभी सामने नहीं आने दिया।'

आडवाणी रेस में आगे थे, लेकिन संतों ने मोदी को चुना

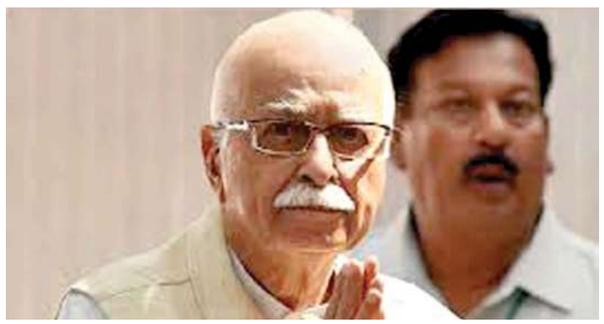

मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। रविंद्र पुरी कहते हैं, 'संत समाज ने 2010 से ही अलग-अलग मंचों पर नरेंद्र मोदी का नाम लेना शुरू कर दिया था। कुंभ की धर्म संसद में तो उनके नाम पर मुहर लगी थी। दावेदारों में लालकृष्ण आडवाणी बहुत आगे थे, लेकिन संत समाज मानता था कि नरेंद्र मोदी पक्के सनातनी हैं। सनातन धर्म की रक्षा वही कर सकते हैं। इसलिए संतों ने एकमत से उन्हें चुना।'इस प्रस्ताव पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सीधे कुछ नहीं कहा। इतना जरूर कहा कि संतों की वाणी ही देववाणी है। तब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राजनाथ सिंह ने कहा कि संतों की भावना हम तक आई है। इससे अलग कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। मैं ये प्रस्ताव ऊपर तक ले जाऊंगा।

कुल मतदाता	पुरुष	महिला	मतदान केंद्र
1,55,24,858	83.49 लाख	71.73 लाख	13033

आप-दा बनाम अंगद का पांव

सुरेश व्यास
(वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक)

चुनाव दिल्ली विधानसभा का है और नजरें पूरे देश की लगी है। लाजिमी है देश की राजधानी में सरकार बनने का सवाल है तो नजरें लगेगी ही। वैसे भी दिल्ली के हर चुनाव पर देश की नजर रहती है, चाहे चुनाव जेनयू छात्र संघ के हो या फिर एमसीडी यानी म्यूनिसीपल कॉरपोरेशन दिल्ली के। लोग दरअसल, दिल्ली के चुनावों से राष्ट्रीय दलों का दूध और पानी नापते रहे हैं, भले ही इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़े या नहीं पड़े। फिजां तो इस बार भी ऐसी ही बनी है।

चुनाव आयोग की ओर से दिल्ली विधानसभा सीटों की 70 सीटों के लिए तारीखों का ऐलान होने से पहले ही दिल्ली की राजनीति भरी सर्दी और कोहरे में भी इतनी गर्मा गई कि इस बार के चुनाव राष्ट्रीय नेताओं की अस्मिता के चुनाव के रूप में नजर आने लगे हैं। इसके संकेत तो पिछले 27 साल से दिल्ली की सत्ता के लिए तरह रही भाजपा के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक आम आदमी पार्टी यानी आप को आप-दा पुकार कर दे चुके हैं। कांग्रेस इन चुनावों में इंडिया गठबंधन की ताकत को ताक में रखकर पिछले तीन चुनावों से अंगज के पांव की तरह डटी अरविंद केजरीवाल की पार्टी को टक्कर देने के लिए मैदान में है। दिल्ली चुनाव को लेकर ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, लालू यादव की पार्टी के वारिश तेजस्वी यादव सरीखे नेता इंडिया गठबंधन की प्रासंगिकता को लेकर सवाल उठा चुके हैं। वहीं केंद्र में सत्ताधारी एनडीए के सहयोगी रामदास अठावले की पार्टी अपने दम पर आप और भाजपा के सामने खम ठोक रही है।

ऐसे में देखा जाए तो गुजरात चुनाव में मत प्रतिशत और पंजाब में सरकार बनाने के बाद राष्ट्रीय दल के रूप में उभरी आम आदमी पार्टी के सामने हर कोई खम ठोक रहा है यानी केजरीवाल की आप एक तरफ और बाकी दल दूसरी तरफ। ये हकीकत भी है। इस बार दिल्ली के चुनाव आप बनाम अन्य है। चुनाव की घोषणा के बाद तो ये साफ हो गया कि ये चुनाव केजरीवाल के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। आप का मुकाबला है भाजपा या कांग्रेस से। कांग्रेस भले ही मजबूत स्थिति में नहीं हो, लेकिन भाजपा ने दिल्ली के चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया और वह इस अकेली विधानसभा का चुनाव देश के आम चुनाव की तरह लड़ने को आतुर है। यही वजह है कि भाजपा ने ओपनिंग बेट्समैन के रूप में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतार दिया। उन्होंने आप की सरकार को दिल्ली के लिए आप-दा कह डाला तो शीशमहल के बहाने दिल्ली की आप सरकार को भ्रष्टाचार के मामले में घेरने की कोशिश कर ली। इसके बाद अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा और अनुराग ठाकुर ने शराब घोटाले के बहाने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया तो भाजपा के बाकी नेता पूर्वांचल के मतदाताओं के सहारे नैय्या पार लगाने की कोशिश में हैं, क्योंकि दिल्ली के मतदाताओं का 42 फीसदी इसी के नामे लिखा है।

दरअसल, भाजपा दिल्ली की सत्ता में वापस लौटने के लिए पिछले 27 साल से इंतजार कर रही है। हालांकि इस दौरान उसका मत प्रतिशत लगातार बढ़ा है, लेकिन सीटें दहाई की संख्या तक भी नहीं पहुंच पाई। मदनलाल खुराना, साहिब सिहं वर्मा और सुषमा स्वराज के बाद दिल्ली का कोई नेता न तो शीला दीक्षित और न ही बाद में अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे पाया। भले ही भाजपा पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सातों सीटें जीता, लेकिन दिल्ली विधानसभा में कमल खिलाना उसके लिए अब भी दिवास्वप्न ही है। शायद यही वजह है कि भाजपा ने चुनावों के ऐलान से पहले ही आक्रामकता को अपना लिया है। वरिष्ठ पत्रकार केपी मल्लिक कहते हैं कि देश में फिर एक बार मोदी सरकार का सपना साकार करने के बाद भाजपा को लगता है कि दिल्ली नहीं जीती तो क्या जीता। इस वजह से ही उसने पहले तो पीएम मोदी से प्रचार अभियान की शुरुआत करवाई और बाद में भ्रष्टाचार के बहाने राष्ट्रीय मुद्दा अपनाने की कोशिश की। केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते सरकारी आवास में करवाए गए खर्चे को लेकर शीशमहल के बहाने आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की गई तो आम आदमी पार्टी ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकारी आवास पर हुए खर्चों के बहाने राजमहल का मुद्दा सामने ला दिया। पूर्वांचल के मतदाताओं को लुभाने के लिए भाजपा सम्मान के नाम पर छठ पूजा का मुद्दा ले आई, लेकिन उसे लगता है कि राष्ट्रीय मुद्दों के बहाने नैय्या पार नहीं लगनी और देश की जनता भी रेवड़ी के प्रसाद से ही राजी रहती है तो अब उसने महिला सहायता और 300 यूनिट फ्री बिजली पर फोकस करना शुरू किया है। यानी वह सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी करेगा, वाली रणनीति पर आ गई है।

चुनाव कार्यक्रम

नामांकन 10 से 17 जनवरी
नाम वापसी 20 जनवरी
मतदान 5 फरवरी
मतगणना 8 फरवरी

कुल विधानसभा सीटें 70

दलीय स्थिति	2020	2015	2013
आप	67	62	28
भाजपा	08	03	31
कांग्रेस	00	00	08

दूसरी ओर कांग्रेस भी केजरीवाल को ही घेर रही है। कमान पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मकान ने सम्भाल रखी है, लेकिन उन्हें भी केजरीवाल से मुकाबले का कोई समीकरण समझ नहीं आ रहा। हालांकि कांग्रेस ने राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह गारंटियों का कार्ड खेला है, लेकिन इसका असर मतदाताओं पर नजर नहीं आ रहा। दिक्कत यह है कि कांग्रेस कोई नेरेटिव खड़ा कर पाने में कामयाब होती नहीं दिख रही। फिर हरियाणा और महाराष्ट्र में मिली पराजय भी कांग्रेस अभी तक नहीं भुला पाई है। अब भी उसके नेताओं में आत्मविश्वास नजर नहीं आता। दिल्ली की राजनीति पर गहरी नजर रखने वाले पत्रकार बाबुल वी. राज कहते हैं कि कांग्रेस केजरीवाल को नुकसान तो पहुंचा सकती है, लेकिन खुद का भला करने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस दलितों और अल्पसंख्यकों के सहारे आम आदमी पार्टी के वोट जरूर काट सकती है, लेकिन इसका फायदा उसकी बजाय भाजपा को ही ज्यादा होने के आसार नजर आते हैं। इससे केजरीवाल की सत्ता जाती है तो कांग्रेस इससे भले ही खुश हो जाए कि उसने केजरीवाल को तो नहीं आने दिया। इन चुनावों में कांग्रेस को इससे ज्यादा कुछ ज्यादा मिलता नहीं दिखता। यानी कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है।

अब आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसके नाम एक कीर्तिमान है। आन्दोलन से उपजी आम आदमी पार्टी सम्भवतः देश की एक मात्र पार्टी है, जिसने महज एक दशक में वह राष्ट्रीय राजनीतिक दल पा लिया। दिल्ली व पंजाब सहित दो राज्यों में सरकार बना ली। बाकी राज्यों में उपस्थिति दर्ज करवा चुकी। पीएम मोदी के गृह राज्य में सर्वाधिक वोट हासिल कर दूसरे नम्बर की पार्टी बन गई। दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए काम और पैठ की बदौलत अब वह चौथी बार दिल्ली की सत्ता में आने के लिए लड़ रही है। राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश कुमार की राय में हालांकि केजरीवाल को सत्ताविरोधी लहर का डर है, लेकिन किए हुए काम का आत्मविश्वास ही माना जाना चाहिए कि आप भाजपा की कट्टरविरोधी पार्टी के रूप में उभरी है। अब भी उसका मुकाबला भाजपा से ही है। कांग्रेस भले ही चुनावों को त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश करे, लेकिन अभी की स्थिति तो केजरीवाल बनाम भाजपा ही नजर आती है।

आम लोग भी मानते हैं कि मॉडल स्कूल, मौहल्ला क्लिनिक, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा और मुफ्त बिजली पानी जैसी सुविधाओं ने दिल्ली के लोगों को बहुत राहत पहुंचाई है। हालांकि भाजपा ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सुभाष जैन जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर भ्रष्टाचार का नैरेटिव बनाया, लेकिन लोग इसे कम तवज्जो देते हैं। फिर भी इससे आप की छवि पर असर तो पड़ा ही है।

अब सवाल यह है कि चुनाव में कौन कितने पानी में। इस बात में कोई दो राय नहीं कि भाजपा ने दिल्ली के चुनाव को अपनी मूंछ का सवाल बना रखा है, तभी तो उसने पीएम मोदी को आगे कर प्रचार अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस भी हवा में हाथ पैर पार रही है। शीला दीक्षित और उनके कामों को याद किया जा रहा है, मगर गाड़ी पीछे ही है। केजरीवाल के पास गिनाने को काम है और विक्टिम कार्ड भी कि कैसे भाजपा ने शराब घोटाले के नाम पर उन्हें और उनकी सरकार को घेरने की कोशिश की। नेताओं को जेल में डाला, लेकिन फूटी कौड़ी भी कहीं से नहीं मिली। यानी करेप्शन का भाजपा का नैरेटिव तोड़ने के लिए केजरीवाल के पास भले ही बहुत कुछ है, लेकिन इस बार वे भाजपा के चक्रव्यू में आ फंसे है, शायद खुद केजरीवाल भी इसे मान ही रहे होंगे। नामांकन शुरू हो चुके हैं। मतदान 5 फरवरी को होगा। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। तभी पता चलेगा, कौन कितना पानी में।

आप का इतिहास

अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी साल 2013 में पहली बार चुनावी राजनीति में उतरी और दिल्ली विधानसभा के अपने पहले ही चुनाव में 28 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया। हालांकि इस चुनाव में भाजपा 31 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी, लेकिन कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया और राजस्व सेवा की नौकरी से राजनीति में आए अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने। उनकी सरकार भले ही महज 49 दिन चली और फरवरी 2014 में केजरीवाल ने संख्या बल की कमी का हवाला देकर यह कहते हुए कुर्सी छोड़ दी कि वे लोकपाल बिल पास करवाने में नाकाम रहे हैं। इसलिए चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटेंगे। इसके बाद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने दिल्ली की राजनीति में अंगद की तरह ऐसा पैर जमाया कि पिछले दो चुनावों में भाजपा और कांग्रेस केजरीवाल के आसपास भी नहीं दिखी। भाजपा तो 70 सीटों वाली विधानसभा में दहाई की संख्या तक नहीं पहुंच पाई और कांग्रेस एक सीट को भी तरस रही है।

इन्द्रप्रस्थ का 'इन्द्रासन'

दिनेश जोशी
स्वतंत्र पत्रकार, लेखक

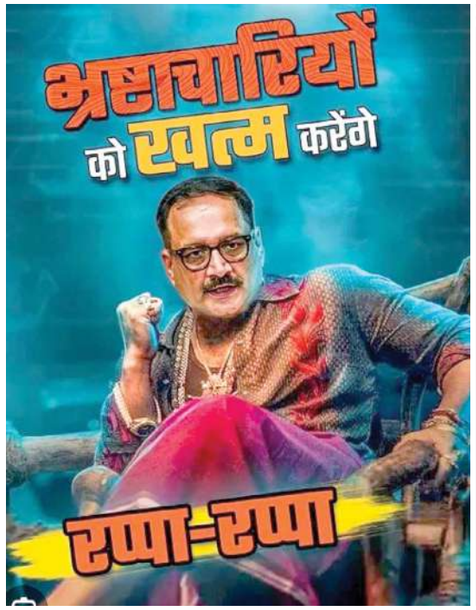

मे हरबान... कद्रदान... फूलदान... पीकदान... सॉरी, अपने देश की राजधानी दिल्ली यानी 'इन्द्रप्रस्थ' के विधानसभा चुनावों का माहौल इन दिनों 'पीक' पर है, इसलिए कुछ ऐसा—वैसा स्वतःस्फूर्त लिख जाता है। चुनाव की भी भली कही, शादी का मंडप सज चुका हो जैसे... हर पार्टी बाराती बनकर अपनी-अपनी बैंड बजाने में जुटी हो जैसे... और जनता इनकी बारात की दुल्हन हो जैसे...। बेचारी जनता को बार-बार यह सोचने पर मजबूर किया जाता है कि आखिर उसे इस बार किसके साथ फेरे लेने चाहिए।

हर बार की तरह पार्टियों की चुनावी घोषणाएं इस बार भी किसी फिल्मी ट्रेलर से कम नहीं हैं। "फ्री बिजली, फ्री पानी, और साथ में फ्री वाई-फाई भी!" लगता है जैसे नेताजी ने दिल्ली को सिम कार्ड में बदल दिया हो – हर सुविधा मुफ्त! जनता सोचती है, "वाह! ऐसे ऑफर तो अमेज़न पर भी नहीं मिलते।" वोटर की कोहनी पर लगा मुफ्तखोरी का गुड़ उसे भले ही विवेकहीन बना दे, मगर स्साला चाहिए सबकुछ मुफ्त। इस चक्कर में बिजली कंपनियां भले ही दिवालिया हो जाए मगर पब्लिक को इतना मुफ्तखोर बना दो कि उसके हाड़ ही हिलने से मना कर दे।

चुनावी पूर्वजों ने आरक्षण को जीत की वैतरणी माना था, लेकिन आधुनिक राजनेताओं ने मुफ्तखोरी की नब्ज पकड़ ली है। इन्द्रासन अब चाहे जिसका हो, लेकिन हम तो नेताओं और नेताणियों के जीवन—मरण जैसा माहौल देखकर ही गद्गद् हैं। राजधानी की सड़कें पोस्टरों से अटी हैं तो हर गली-मोहल्ले में लगे नेताजी के बड़े-बड़े कटआउट मनुष्य का अपना विराट रूप दिखाने का असफल प्रयास लगता है। कोई हाथ जोड़े दिखता है, तो कोई खीसें निपोरते हुए जनता का दिल जीतने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ भी कहिए, असली मज़ा रैलियों में आता है। नेता जी कहते हैं, "हमने दिल्ली को लंदन बना दिया है।" और जनता, जो रोज़ ट्रैफिक में फंसी होती है, सोचती है, "लंदन तो पता नहीं, पर ट्रैफिक ने दिल्ली को बेंगलुरु जरूर बना दिया है।"

एक और मजेदार नज़ारा उम्मीदवारों की दावेदारी का है। सभी दलों को जिताउ, टिकाउ लेकिन बिकाउ न हो ऐसा दावेदार चाहिए। पर पिछले दो दशकों से लगता है ऐसे दावेदारों का भारी अकाल पड़ा हुआ है। अब तो किसी पार्टी से टिकट कट गया तो तुरंत दूसरी पार्टी में शामिल। इन पार्टियों की एक टीम तो पुष्पगुच्छ लिए ही खड़ी रहती है कि 'आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा...।' ऐसा लगता है जैसे पार्टियों के बीच कोई 'हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट' का कनटेस्ट चल रहा हो।

चुनाव के दिन, जनता बेचारी कसमसाती है। बूथ तक जाते हुए मन में सवाल होता है, "इस बार किसे चुनें?" चुनाव बाद के दिन और भी मजेदार होंगे। हारने वाला कहेगा, "ईवीएम में गड़बड़ी हुई है।" जीतने वाला कहेगा, "जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है।"

जनता भी यही सोचती है कि यह नाटक तो हर पांच साल में खेला जाना है। फिर भी, उम्मीदों के साथ, हर बार नया नेता चुन लेती है, मानो किसी जादू की छड़ी से सबकुछ बदल जाएगा। लेकिन हकीकत यही है – चुनाव खत्म, और सबकुछ वापस वैसे का वैसा! यानी खेल खतम, पैसा हजम...।

ट्रम्प की आग या ट्रम्प से आग?

- अमेरिका के जंगलों में आग लगना अब कोई खबर नहीं, बल्कि एक वार्षिक परंपरा बन गई है। हर साल वहां जंगलों में आग लगती है और पूरी दुनिया के अखबारों में सुर्खियां बन जाती है। लगता है, जैसे जंगल खुद सोच रहे हों, "अरे भाई, हम भी ट्रेंड में आना चाहते हैं!"
- वैसे देखा जाए तो यह आग सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि आधुनिक मानवता की "चेतावनी" है। वैज्ञानिक बताते हैं कि ग्लोबल वॉर्मिंग और पर्यावरणीय असंतुलन इसके मुख्य कारण हैं। लेकिन कोई नेता इस विषय पर गंभीरता से बात करे, ऐसा कैसे हो सकता है। नये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने यह सोचते हुए कि आग को आग ही रोक सकती है, सजायाफ्ता कैदियों को आग बुझाने के काम में झोंक दिया है। उन्हें उनकी सजा में रियायत देने का लालच दिया गया है।
- कुछ वीडियो में देखा है कि हेलीकॉप्टरों से पानी गिराया जा रहा है। लेकिन पानी इतना कम है कि लगता है हेलीकॉप्टर जंगल के साथ "होली" खेल रहा हो। आग कहती है, "वाह, क्या प्रयास है! थोड़ा और जोर लगाओ।"
- सोशल मीडिया पर पर्यावरण प्रेमियों की भी यकायक बाढ़ आ गई है। हर कोई ग्रीन डीपी लगाकर दिखा रहा है कि वह पृथ्वी का सबसे बड़ा शुभचिंतक है। लेकिन, जब बिजली का एसी ऑन करके यह पोस्ट लिखी जाती है, तो ग्लोबल वॉर्मिंग भी सोचती है, "क्या मजाक है यार!"
- सबसे मजेदार पहलू यह है कि जब दुनिया में कहीं भी कोई घटना होती है, तो भारत के ट्विटर यूजर्स तुरंत इसका "मेमे" बनाकर वायरल कर देते हैं। कोई कहता है, "अमेरिका के जंगलों की आग हमारे मोहल्ले के कचरे की आग से भी ज्यादा खराब है!" अब बताओ ये कितने दिलजले होंगे?

नए मोड़ पर राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी

संघर्ष, संतुलन और सियासत

विवेक श्रीवास्तव
वरिष्ठ पत्रकार

राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी इन दिनों बदलाव, संघर्ष और संतुलन के नए दौर से गुजर रही है। प्रशासनिक गलियारों में हर तरफ एक नई हलचल है। जहां एक ओर मुख्य सचिव सुधांशु पंत के नेतृत्व में ब्यूरोक्रेसी को एक नई दिशा देने की कोशिशें की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर अफसरशाही के भीतर गुटबाजी और संतुलन का संकट भी गहराता जा रहा है।

मुख्य सचिव की दमदार एंट्री

31 दिसंबर 2022 को निवर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा के रिटायर होने के बाद सुधांशु पंत ने प्रदेश के मुख्य सचिव का पदभार संभाला। केंद्र से लौटने के बाद पंत की नियुक्ति को लेकर बड़े राजनीतिक संकेत देखे गए। उनकी कार्यशैली, फाइलों पर तेजी से निर्णय लेना और स्पष्ट दृष्टिकोण ने उन्हें एक प्रभावी प्रशासक के रूप में स्थापित किया। शुरुआत में पंत ने औचक निरीक्षण और त्वरित फैसलों से अपनी छवि को मजबूत किया।

हालांकि, हाल ही में जैसलमेर के दौरे में स्थानीय अफसरों द्वारा उन्हें बिना फिटनेस सर्टिफिकेट वाले वाहन में घुमाने की घटना ने प्रशासनिक नियंत्रण पर सवाल खड़े कर दिए। यह घटना संकेत देती है कि मुख्य सचिव का प्रभावशाली आरंभ धीरे-धीरे सामान्य होता जा रहा है।

ब्यूरोक्रेसी में गुटबाजी और संघर्ष

मुख्य सचिव के साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संतुलन स्थापित करने के लिए शिखर अग्रवाल को सीएमओ एसीएस नियुक्त किया। इससे ब्यूरोक्रेसी में दो ध्रुव बनने लगे। एक ओर सुधांशु पंत का खेमा है, तो दूसरी ओर शिखर अग्रवाल का। यह विभाजन सचिवालय में स्पष्ट तौर पर दिखा, जब सीएम के निरीक्षण के दौरान अग्रवाल साथ थे, लेकिन मुख्य सचिव पंत नदारद।

सूत्रों के मुताबिक, आईएएस लॉबी भी दो गुटों में बंट चुकी है। शिखर अग्रवाल के करीबी अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। वित्त सचिव अखिल अरोड़ा और उनकी पत्नी अपर्णा अरोड़ा को अहम विभागों में बनाए रखना इसी गुटबाजी का परिणाम माना जा रहा है।

भ्रष्टाचार के आरोप और मुख्य सचिव की चुनौती

राजस्थान कैडर के वरिष्ठ अफसर सुबोध अग्रवाल, जो मुख्य सचिव पद की दौड़ में थे, पर जल जीवन मिशन में करोड़ों के घोटाले के आरोप हैं। ईडी की जांच और छापेमारी के चलते उनका मुख्य सचिव बनना संभव नहीं हुआ। ऐसे में सुधांशु पंत को चुनकर भाजपा नेतृत्व ने स्पष्ट संकेत दिया कि उन्हें एक प्रभावी और साफ-सुथरे प्रशासक की जरूरत है।

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप

ब्यूरोक्रेसी में बढ़ती गुटबाजी का असर राजनीतिक बयानबाजी में भी दिखा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान की सरकार को 'चार इंजन' की सरकार बताया—मुख्यमंत्री-मंत्रियों, ब्यूरोक्रेसी, पूर्व मुख्यमंत्री के गुट और आरएसएस। उनका कहना था कि ये चारों इंजन अलग-अलग दिशाओं में खींच रहे हैं, जिससे सरकार का कामकाज प्रभावित हो रहा है।

आगे का रास्ता

राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी जिस मोड़ पर खड़ी है, वहां संतुलन और प्रभावी नेतृत्व की सख्त जरूरत है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत की चुनौती न केवल गुटबाजी को खत्म करना है, बल्कि प्रशासन को नई ऊर्जा और दिशा भी देनी है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि पंत और शिखर अग्रवाल के बीच यह शक्ति संतुलन ब्यूरोक्रेसी और राज्य के विकास को किस दिशा में ले जाता है।

देखना होगा

राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी इस समय एक दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है। सुधांशु पंत के नेतृत्व, शिखर अग्रवाल के प्रभाव और राजनीतिक दबावों के बीच यह देखना अहम होगा कि प्रदेश की अफसरशाही अपने पुराने ढर्रे से निकलकर नई भूमिका में कैसे खुद को ढालती है। यह दौर राजस्थान के प्रशासनिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ सकता है।

प्रदेश के विकास के लिए कई बड़े फैसले लिए, 4 साल में कितनी बुलंदियां छू पाएंगे देखेंगे सब

अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीं आसमां बाकी है

राजेश कसेरा
वरिष्ठ पत्रकार,
राजनीतिक विश्लेषक

राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने एक साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। इस दौरान कई बड़े काम हुए तो अधिकांश कामों पर सवाल भी खड़े हुए। जिन मुद्दों को लेकर भाजपा ने कांग्रेस की अशोक गहलोत को सत्ता से दूर किया, उनकी चर्चा साल भर होती रही। इस दौरान लोकसभा चुनाव में राजस्थान में भाजपा बैकफुट पर आ गई तो उप चुनाव में फिर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद और समर्थन मिला। एक साल के दौरान कई बार ऐसे अवसर आए, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पद से हटाने और नया मुख्यमंत्री बनाने की अफवाहें सामने आईं। इसके बावजूद भजनलाल सरकार ने राइजिंग राजस्थान इंवेस्टमेंट समिट, पीकेसी-ईआरसीपी प्रोजेक्ट का शिलान्यास, पेपरलीक माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, युवाओं को रोजगार के अवसर देने जैसे बड़े काम शुरू किए। राज्य सरकार ने दावे किए कि उन्होंने बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण और शहरी विकास, परिवहन और उद्योग समेत विभिन्न क्षेत्रों में काम शुरू किए। ये काम कितने आगे बढ़ेंगे और पूरे होंगे, इसके लिए चार साल सरकार को मिलेंगे।

सीएम का लक्ष्य 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था

...लेकिन पूरा करने के संसाधन ही नहीं

सबको साथ लेकर चलने के दावे करने वाले सीएम भजनलाल शर्मा भले प्रदेश के विकास में के लिए दिन-रात पसीना बहा रहे हों, लेकिन पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ उनके साथी विधायकों को वे अक्सर खटकते रहते हैं। यहां तक कि विपक्ष भी उनको पचा नहीं पा रहा है और पर्ची सरकार का मुखिया संबोधित कर उन पर निशाना साधता रहता है।

...इन सारी चुनौतियों के बीच आने वाले चार साल में कैसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के आर्थिक तंत्र को मजबूत बनाने के साथ बड़ी योजनाओं को धरातल पर साकार करने का काम कर पाएंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी।

राइजिंग राजस्थान इंवेस्टमेंट समिट के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले पांच सालों में 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का दावा किया। जबकि प्रदेश की मौजूदा जीडीपी 186 बिलियन डॉलर यानी 15 लाख 28 हजार करोड़ अनुमानित है। यानी 350 बिलियन डॉलर तक जाने में लगभग अर्थव्यवस्था का आकार दुगने से ज्यादा करना होगा। आर्थिक विशेषज्ञों की मानें तो कोविड के बाद मौजूदा अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है, उसमें पांच सालों में राजस्थान की जीडीपी 350 बिलियन डॉलर को पार कर सकती है। यह बड़ा लक्ष्य नहीं है। मौजूदा जीडीपी ग्रोथ रेट 12 से 13 प्रतिशत चल रही है। पर, यहां बड़ा सवाल यह है कि इस आर्थिक विकास की कीमत प्रदेश क्या चुका रहे है? जिस वित्तीय प्रबंधन के दावे किए जाते हैं, क्या वह विश्वसनीय है? जिस टीम के हाथों में राजस्थान का वित्तीय प्रबंधन है, उन्होंने पिछले पांच सालों में राजस्थान को कहां पहुंचाया है, ये भी बड़ा सवाल है? राजस्थान में वित्त विभाग की कमान बीते 6 साल से ज्यादा समय से अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा संभाले हुए हैं। हाल ये हैं कि प्रदेश पर कर्ज का भार 6 लाख 8 हजार 813 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। बोर्ड-कॉरपोरेशन और पीएसयूज पर ऋण दायित्व करीब सवा लाख करोड़ से ज्यादा है। राजस्थान के खजाने को गिरवी रखकर कर्ज लिया और इतना सब होने के बाद हर साल करीब 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक की रकम ब्याज के रूप में चुका कर रहे हैं। प्रदेश की डीजीपी से इसकी तुलना करें तो कुल ऋण दायित्व करीब 80 से बिलियन डॉलर से ज्यादा हो चुका है।

प्रदेश के आर्थिक हालात को मजबूत बनाना

सबसे बड़ी चुनौती

राजस्थान फिस्कल रेस्पोंसबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट (एफआरबीएम) की हाल में सामने आई रिपोर्ट की मानें तो प्रदेश पर कर्ज का भार 6 लाख 8 हजार 813 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। मार्च-2024 तक यह आंकड़ा 5.70 लाख करोड़ रुपए का था। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अप्रेल से सितंबर-2024 तक के सरकार की ओर से जारी आंकड़ों में भी सामने आया कि कर्ज का यह स्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। प्रदेश की जनसंख्या 8.36 करोड़ है और इस हिसाब से हर व्यक्ति पर कर्ज का बोझ 72 हजार 825 रुपए हो गया है। राज्य सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान कर्ज में करीब 70 हजार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी और होने का अनुमान लगाया। इस हिसाब से सरकार पर हर माह औसतन छह हजार करोड़ से अधिक का कर्ज बढ़ रहा है।

विशेषज्ञों की मानें तो बढ़ते कर्ज का सबसे बड़ा असर ब्याज भुगतान पर पड़ेगा, जिससे सरकार को विकास योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने में मुश्किलें आ सकती हैं। इसके अलावा कर्ज बढ़ने से ये आशंका भी बढ़ जाती हैं कि सरकार को टैक्स बढ़ाकर जनता से अतिरिक्त राजस्व जुटाना पड़े। हालांकि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व का लक्ष्य 1.25 लाख करोड़ रुपए निर्धारित कर रखा है।

राइजिंग राजस्थान से आया 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश जमीन पर उतारना होगा

5 साल में 10 लाख युवाओं को
रोजगार देने का रोडमैप कैसे बनेगा

भजनलाल सरकार ने अपनी 5 साल की सरकार के दौरान 10 लाख से ज्यादा प्रदेश युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की है। इसमें सबसे बड़ी भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की है। इसके अलावा ड्राइवर, पशुधन सहायक, जेल प्रहरी, कंडक्टर, वरिष्ठ अध्यापक पदों की भर्तियां शामिल हैं। इनके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। पर, सरकार सफाईकर्मी भर्ती परीक्षा को बीते एक साल में पूरा नहीं कर पाई तो बाकी की भर्तियों को कैसे पूरा करेंगी, ये सवाल भी उठ रहा है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 के मुताबिक राजस्थान में बेरोजगारी दर 4.2% है। पंजाब की सबसे ज्यादा 5.5% तो राजस्थान दूसरे नंबर पर है। प्रदेश में सरकार बदलने के बावजूद प्रदेश का बेरोजगारी दर के लिहाज से देश के पहले पांच राज्यों में शुमार होना निराशाजनक है। प्रदेश में बीते कुछ वर्षों में एक के बाद एक रद्द होती भर्तियों और कोर्ट में अटके मामलों को लेकर भी बेरोजगारी दर में इजाफे को बड़ा कारण माना गया। भजनलाल सरकार के समक्ष यही चुनौती सबसे बड़ी है कि वे युवाओं को रोजगार देने की दिशा में कैसे ठोस कार्ययोजनाओं को बनाएंगे और उन्हें साकार करेंगे।

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत कुल 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू हुए थे। इनमें से लगभग 32 लाख करोड़ रुपए के 261 एमओयू एक हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि वाले हैं। 100 करोड़ से अधिक और 1 हजार करोड़ रुपए से कम राशि वाले एमओयू की संख्या 1 हजार 678 है, जिनकी कुल राशि 3.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। वहीं 100 करोड़ रुपए तक के एमओयू की संख्या 9 हजार 726 है और इनकी कुल राशि लगभग 90 हजार करोड़ रुपए है। जयपुर में गत वर्ष 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित हुए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हस्ताक्षरित एमओयू की प्रगति और विस्तृत रिपोर्ट को वे दिसंबर-2025 में प्रदेशवासियों के सामने प्रस्तुत करेंगे। इस काम को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए सरकार ने औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी विजन और रोडमैप के साथ काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए त्रि-स्तरीय समीक्षा व्यवस्था के तहत एक हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि वाले एमओयू की समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर होगी। 100 करोड़ से लेकर 1 हजार करोड़ रुपए तक की राशि वाले एमओयू की समीक्षा मुख्य सचिव स्तर पर पाक्षिक रूप से होगी। वहीं 100 करोड़ रुपए से कम राशि वाले एमओयू की समीक्षा विभागीय सचिव स्तर पर साप्ताहिक रूप से की जाएगी। भजनलाल सरकार निवेश को जमीन पर लाने की कार्ययोजना भले अच्छे से बना रही हो, पर प्रदेश में पूर्व सरकारों के समय हुए ऐसे प्रयासों के अनुभव भी बेहद कड़वे रहे हैं।

गहलोत सरकार में चौथे साल में इन्वेस्ट राजस्थान समिट में हुए 12.53 लाख करोड़ के 4,195 एमओयू

पिछली गहलोत सरकार में चौथे साल में इन्वेस्ट राजस्थान समिट हुआ था। इसमें 12.53 लाख करोड़ के 4 हजार 195 एमओयू हुए थे। जबकि निवेश आया 25 हजार 975 करोड़ रुपए का। यानी केवल 2.07 प्रतिशत। वसुंधरा सरकार में 2015 में रिसर्जेंट राजस्थान समिट में 3.37 लाख करोड़ के 470 एमओयू हुए थे। इसमें भी निवेश आया 33 हजार करोड़ रुपए का यानी 10 प्रतिशत। वसुंधरा सरकार के समय 1.20 लाख करोड़ के करार कुछ महीनों में निरस्त हो गए थे। 4% प्रोजेक्ट लिटिगेशन में फंस गए थे तो इतने ही लंबित रह गए। ऐसे ही गहलोत सरकार के 604 करार आगे नहीं बढ़े तो 1378 खारिज हो गए। निवेशकों ने लिखकर दिया कि उनको न जमीन मिली न ही बेसिक इन्फ्रास्टक्चर। ऐसे में बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि बड़ा सवाल यही है कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत जैसे अनुभवी और दिग्गज मुख्यमंत्री अपने दावे के मुताबिक निवेश नहीं ला पाए तो पहली बार मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा कैसे लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे? लेकिन इसका जवाब तलाशें तो भजनलाल सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले साल में इस काम को किया। उनके पास चार साल बाकी हैं। सरकार के पास निवेशकों की तमाम शंकाओं और मुश्किलों को दूर कर उससे निवेश कराने का पूरा मौका है। सरकार ने हर एक निवेशक से वादे के मुताबिक निवेश करवाने के लिए एक आईएएस और आरएएस अधिकारियों को नियुक्त किया है। इनकी जिम्मेदारी होगी कि वे उन्हें मनाएं, उनके निवेश में आ रही अड़चन दूर करें।

राजनीतिक अड़चनें भी कम नहीं, सबको साथ नहीं ले पाए एक साल में

पहली बार मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा के पास सरकार या विधायिकी का पुराना अनुभव नहीं हैं। लेकिन सत्ता और संगठन के बीच वे लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उनको प्रदेश की कमान सौंपी तो राजनीतिक भूचाल आ गया। किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि उनके नाम की पर्ची को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की राह देख रहीं वसुंधरा राजे को खोलना होगा। बीते एक साल में भजनलाल शर्मा ने भले सबको साथ में लेकर सरकार चलाने के भरसक प्रयास किए, लेकिन प्रदेश की राजनीति के मैदान में लंबे समय से टिके दिग्गजों को वे साध नहीं पाए। सालभर में ऐसे कई मौके आए, जब ये बातें हवा में बहीं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री बदलने वाला है। लेकिन इस दिशा में किसी ने न तो सोचा और न ध्यान दिया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने भजनलाल शर्मा के नाम को तय किया तो इसके पीछे के सारे सियासी समीकरण क्या होंगे? फिर भी बीते एक साल में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री की पूरी परीक्षा ली। कैबिनेट में शामिल होने के बावजूद मंत्री किरोड़ी लाल मीणा सरकार और पार्टी की परेशानियों को बढ़ाते रहे हैं। सरकार में होने के बावजूद बीते एक साल में उन्होंने अपने विभाग से संबंधित किसी बड़े फैसले पर काम नहीं किया। इसी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पार्टी की ओर से कोई भूमिका तय नहीं होने से उनके समर्थक भी पर्दे के पीछे से भजनलाल सरकार के लिए अड़चनें पैदा कर रहे हैं। वसुंधरा राजे की उप चुनाव के बाद बढ़ी सक्रियता ने भी सियासत के कई समीकरणों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा राजेन्द्र राठौड़, सतीश पूनिया जैसे वरिष्ठ नेताओं को राजस्थान में संतुष्टपूर्ण भूमिका नहीं मिलने से अटकलों का बाजार गर्म बना रहता है। इधर, विपक्ष के मजबूत नेताओं अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, शांति धारीवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास को काउंटर करने के लिए भी भजनलाल शर्मा और उनकी नई टीम कमजोर दिखाई देती है।

> *कैबिनेट में किरोड़ी मीणा के अलावा ऐसा कोई दूसरा बड़ा नेता नहीं है तो विपक्ष पर करारा पलटवार कर सके। इस भूमिका को प्रदेश प्रभारी राधामोहन अग्रवाल, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र राठौड़ निभा रहे हैं। आने वाले चार साल में विपक्ष को शांत रखने के लिए भी भजनलाल सरकार को मजबूत प्लान बनाना ही होगा।'*

बजट की घोषणाएं बाकी, लाल डायरी खोयी...

चुनावी साल होने की वजह से भजनलाल सरकार का पूर्ण बजट जुलाई में लाया गया। बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गईं। बजट पास होने से पहले ही मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और बड़े अफसर को उसे धरातल पर उतारने के लिए टास्क दे दिया। इस कदम की विपक्ष ने जमकर आलोचना भी की और विधानसभा में सवाल भी उठाए। ऐसे में बजट की आधी घोषणाएं बीते छह महीने में पूरी नहीं हो पाईं। इस बार सरकार ने शीतकालीन सत्र में बजट को लाने के संकेत दिए हैं, जिससे कि बजट की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम पूरा कर सकें। इसी तरह से विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने लाल डायरी को बड़ा मुद्दा बनाया था। चुनावी सभाओं में पीएम मोदी तक ने लाल डायरी का जिक्र करते हुए सरकार बनने पर इसमें लगे आरोपों पर जांच की बात कही थी। सत्ता में आने के बाद लाल डायरी पर चुप्पी है। इस मुद्दे को एक तरह से भुला दिया है। बीते एक साल में सरकार या पार्टी की ओर से इस पर कोई बात नहीं की गई।

वन स्टेट वन इलेक्शन पर काम अधूरा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वन नेशन-वन इलेक्शन की तर्ज पर प्रदेश की भजनलाल सरकार ने वन स्टेट-वन इलेक्शन के तहत निकायों और पंचायत के एक साथ चुनाव करवाने घोषणा की। जिन स्थानीय निकायों के चुनाव जनवरी में बाकी थे, उन 49 शहरी निकायों में प्रशासक लगा दिए हैं। वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर डिटेल रोडमैप नहीं दिया। इसके अलावा 7000 के आसपास पंचायतों में भी प्रशासक लगाए जाने हैं। लेकिन इस दिशा में काम आगे नहीं बढ़ रहा है। इधर, कानूनी विशेषज्ञों की मानें तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 5 साल में करवाया जाना अनिवार्य है। आपात स्थिति को छोड़कर चुनाव टालने का कोई प्रावधान नहीं है। हाल में पंजाब में चुनाव टालने पर सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा चुका है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर ली। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने कहा कि चुनाव टालना संविधान विरोधी कदम है, हम चुप नहीं बैठेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। सरपंच संघ ने भी विरोध जताना शुरू कर दिया। जनवरी में ही 6975 ग्राम पंचायतों, मार्च में 704 ग्राम पंचायतों और अक्टूबर में 3847 ग्राम पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इन सबके एक साथ चुनाव करवाने के लिए आधी पंचायतों के चुनाव आगे पीछे करने होंगे। दिसंबर 2025 में 21 जिला परिषदों, सितंबर-अक्टूबर 2026 में 8 जिला परिषदों और दिसंबर 2026 में 4 जिला परिषदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसी तरह दिसंबर 2025 में 222 पंचायत समिति के मेंबर और प्रधानों का कार्यकाल पूरा होगा, सितंबर 2026 में 78, अक्टूबर 2026 में 22 और दिसंबर 2026 में 38 पंचायत समितियों का कार्यकाल पूरा हो रहा है।

> *वन स्टेट वन इलेक्शन पर विचार के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाने का प्रस्ताव करीब तीन महीने से सीएमओ में लंबित है। अब तक सीएम के स्तर पर मंजूरी मिलना बाकी है। इसके अलावा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धाराओं में संशोधन करना होगा।*

जल्दबाजी का फैसला या चुनावी रणनीति?

राजनीतिक लाभ उठाने की संभावना से भी इनकार नहीं
आर्थिक हालात व प्रशासनिक दुविधाएं भी कम नहीं

राकेश गांधी
वरिष्ठ पत्रकार

मतदाताओं को रिझाने के लिए कई बार सत्ताधारी राजनीतिक दल जल्दबाजी में ऐसे कदम उठा लेते हैं, जो जोखिमभरे होने के साथ ही किसी भी प्रदेश की आर्थिक तबीयत नासाज करने के लिए काफी होते हैं। राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पिछली कांग्रेस सरकार ने चुनाव से कुछ ही पूर्व जिलों की संख्या बढ़ाकर अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने उसे सत्ता विहीन ही कर दिया। हालांकि प्रदेश में प्रशासनिक दृष्टि से कई बड़े कस्बों को जिलों में तब्दील करने की मांग लम्बे समय से चली आ रही थी, लेकिन बगैर योजनाबद्ध तरीके के उठाया गया ये कदम कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। सत्ता जैसे ही भाजपा के हाथों में आई, उसने तत्काल कांग्रेस के इस फैसले को बदल दिया और कई जिलों को फिर से भंग कर दिया। राजनीतिक परिस्थितियां भले ही कुछ भी रही हो, वास्तविक तौर पर विश्लेषण किया जाए तो ये स्पष्ट है कि कांग्रेस ने ठोस व योजनाबद्ध तरीके से जिले बढ़ाने का कदम नहीं उठाया। यदि वित्तीय व प्रशासनिक दृष्टि से पूरी तरह सोच-समझकर ये प्रयास किया जाता तो किसी भी अन्य पार्टी के लिए ये फैसला पलटना आसान नहीं होता।

माना कि जिलों की संख्या बढ़ाना या घटाना सरकारों के दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब है। कांग्रेस ने इसे प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और विकास के लिए आवश्यक समझा होगा, जबकि भाजपा ने इसे प्रशासनिक सरलता और आर्थिक बचत के लिए उचित माना हो। दोनों पार्टियों के फैसलों के पीछे राजनीतिक उद्देश्य भी रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के जिले बढ़ाने के कदम ने जनता के एक हिस्से का समर्थन हासिल किया, लेकिन इसकी दीर्घकालिक सफलता प्रशासनिक क्षमता और नए जिलों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर थी।

हालांकि, यह निर्णय कई विवादों और आर्थिक बाधाओं के कारण पूर्ण रूप से सफल नहीं माना जा सकता। वहीं भाजपा ने जिलों की संख्या कम करके कांग्रेस को यह संदेश दिया है कि वह राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से कांग्रेस के फैसलों को चुनौती देने और उन्हें कमजोर करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्रयास भाजपा द्वारा खुद को "प्रभावी प्रशासन और वित्तीय अनुशासन" की पार्टी के रूप में प्रस्तुत करने व कांग्रेस को "वोट बैंक राजनीति" और "अव्यवस्थित फैसलों" की पार्टी के रूप में चित्रित करने का भी हो सकता है। यदि प्रदेश के आर्थिक हालात व भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सही मायने में विश्लेषण किया जाए तो भाजपा सरकार द्वारा जिलों को कम करने का वास्तविक कारण प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना, वित्तीय जिम्मेदारी निभाना और क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखना समझा जा सकता है। साथ ही, यह कांग्रेस की "लोकलुभावन राजनीति" पर सीधा प्रहार और खुद को एक "उत्तरदायी सरकार" के रूप में प्रस्तुत करने की रणनीति का हिस्सा भी कह सकते हैं।

> *राजस्थान में जिलों की संख्या घटाने का फैसला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की तुलना से प्रेरित हो सकता है, लेकिन यह सीधे तौर पर उनके मॉडल को अपनाने का प्रयास नहीं था। **राजस्थान की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के मद्देनजर, भाजपा ने शायद यह महसूस किया हो कि छोटे जिलों का निर्माण यहां व्यावहारिक नहीं है।** यह कदम राज्य की प्रशासनिक जरूरतों, आर्थिक विवेक, और राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है और राजस्थान की विशिष्ट परिस्थितियों पर आधारित है।*

अपने फैसले को भुना नहीं सकी कांग्रेस

भाजपा ने दिया प्रशासनिक व आर्थिक दुविधाओं का हवाला

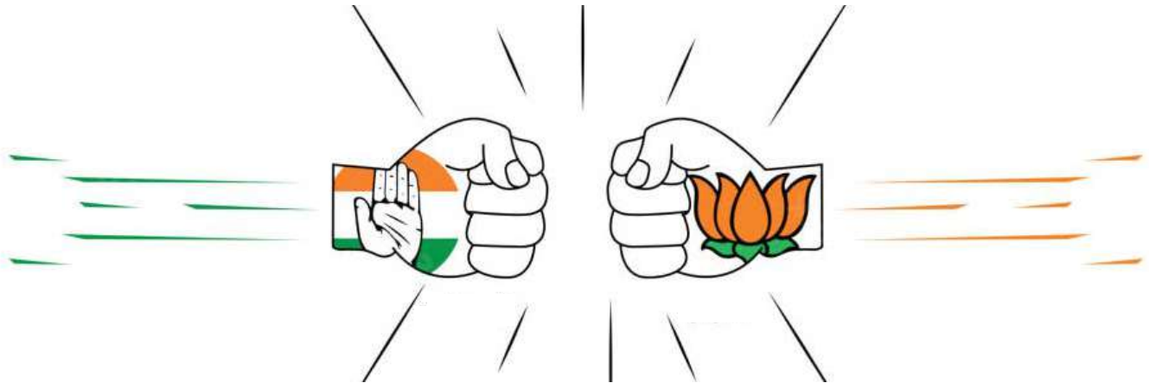

जनता के समक्ष ये सवाल उठना लाजिमी है कि कांग्रेस ने चुनाव से कुछ समय पूर्व ही जिलों की संख्या क्यों बढ़ाई? हालांकि जनता अच्छे से समझती है कि जिलों को बढ़ाना या घटाना अक्सर राजनीतिक, प्रशासनिक, और सामाजिक कारणों से जुड़ा होता है। नए जिलों से स्थानीय स्तर पर शासन और विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद थी। नए जिले बनाना सरकार के लिए एक लोकप्रिय निर्णय हो सकता है, क्योंकि इससे स्थानीय स्तर पर जनता में सकारात्मक संदेश जाता है। यह क्षेत्रीय नेताओं और जनता को खुश करने की रणनीति हो सकती है। नए जिलों से इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और रोजगार के अवसर बढ़ाने का भी लक्ष्य था। कांग्रेस सरकार द्वारा राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़ाने के पीछे कई मंशाएं रही होगी, जो राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जा सकती हैं। बड़े जिलों को विभाजित कर छोटे जिले बनाना कांग्रेस का प्रयास था, जिससे स्थानीय प्रशासन को मजबूत किया जा सके। छोटे जिलों में लोगों की समस्याओं का समाधान जल्दी और प्रभावी तरीके से हो सकता है। कई क्षेत्रों में लंबे समय से नए जिले बनाने की मांग चल रही थी। कांग्रेस ने इन मांगों को पूरा करके जनता का समर्थन पाने की कोशिश की। कुछ क्षेत्रों में जनता ने नए जिलों का स्वागत किया। प्रशासनिक कार्यों में तेजी आई, और कई स्थानों पर विकास परियोजनाओं को बल मिला। जिन क्षेत्रों को नए जिले का दर्जा मिला, वहां कांग्रेस को समर्थन बढ़ाने में मदद मिली। नए जिलों के निर्माण में सरकारी खजाने पर बड़ा बोझ पड़ा। नई प्रशासनिक संरचना स्थापित करने में बहुत खर्च हुआ।

> कई जगहों पर यह तर्क दिया गया कि सरकार ने जिले तो बना दिए, लेकिन जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं को पूरा करने में असमर्थ रही। कुछ क्षेत्रों में जिलों की सीमाओं को लेकर असंतोष और विवाद उभर कर आए। कई जगह लोग इस बात से नाखुश थे कि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया। भाजपा और अन्य विपक्षी दलों ने इसे "चुनावी चाल" और "अव्यावहारिक कदम" करार दिया। भाजपा ने दावा किया कि यह निर्णय केवल जनता को लुभाने के लिए लिया गया, न कि वास्तविक जरूरतों को देखते हुए। नए जिलों से जनता को उच्च स्तर की सेवाओं की उम्मीद थी, लेकिन सीमित संसाधनों के कारण यह हमेशा संभव नहीं हो सका।

भाजपा सरकार भले ही ये कह दे कि ज्यादा जिलों के कारण प्रशासन पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था और समन्वय में कठिनाई हो रही थी। ये सही है कि नए जिलों के निर्माण और संचालन में काफी धन खर्च होता है, लेकिन बेहतर तो ये ही होता कि इस फैसले को बदलने से पहले न केवल आर्थिक, बल्कि प्रशासनिक दृष्टि से भी अच्छे से विचार कर लिया जाता, तो शायद इस फैसले में जल्दबाजी नहीं दिखती। केवल कांग्रेस का फैसला ही बदलना है, इसे किसी भी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। भाजपा सरकार ने संभवतः उन क्षेत्रों में लोकप्रियता बढ़ाने का प्रयास किया, जहां कांग्रेस द्वारा बनाए गए नए जिले विवादास्पद साबित हो रहे थे। भाजपा शासित सरकार ने राजस्थान में जिलों की संख्या कम करके कांग्रेस को कई राजनीतिक और प्रशासनिक संदेश दिए हैं। यह कदम न केवल एक प्रशासनिक निर्णय है, बल्कि कांग्रेस की नीतियों और कार्यप्रणाली पर प्रतिक्रिया और राजनीतिक संदेश देने का तरीका भी समझा जा सकता है। भाजपा ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि कांग्रेस द्वारा किए गए जिलों के विस्तार के निर्णय को वह अव्यावहारिक और अल्पकालिक लाभ के लिए उठाया गया कदम मानती है। कांग्रेस ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए नए जिलों का निर्माण किया, लेकिन इसने आर्थिक और प्रशासनिक बोझ को नजरअंदाज किया। भाजपा ने यह संदेश दिया है कि सरकार के फैसले जनता की वास्तविक जरूरतों और दीर्घकालिक विकास पर आधारित होने चाहिए, न कि केवल वोट बैंक की राजनीति पर।

> कांग्रेस के फैसले को "फिजूलखर्ची" के रूप में प्रस्तुत कर, भाजपा ने खुद को एक जिम्मेदार और व्यावहारिक सरकार के रूप में पेश करने की कोशिश की है। भाजपा ने उन क्षेत्रों में बदलाव किए, जहां कांग्रेस ने नए जिले बनाकर समर्थन जुटाने की कोशिश की थी। यह कदम कांग्रेस के क्षेत्रीय समर्थन आधार को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। यह कदम कांग्रेस की नीतियों को असफल और "नौटंकी" के रूप में दिखाने की भाजपा की बड़ी चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। भाजपा ने यह संकेत भी दिया कि वह कांग्रेस की "बिना गहराई वाली" योजनाओं को पलटने में सक्षम है।

ये कारण हो सकते हैं जिले घटाने के

जिलों की संख्या को कम करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जो प्रशासनिक, आर्थिक, और राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अधिक जिलों के निर्माण से प्रशासनिक ढांचा जटिल हो जाता है। नए जिलों के निर्माण और संचालन में भारी खर्च होता है, जिसमें कलेक्टर कार्यालय, पुलिस विभाग, न्यायपालिका, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थापना शामिल हैं। कांग्रेस द्वारा बनाए गए कई नए जिले व्यावहारिक रूप से छोटे थे और उनकी स्थापना के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना नहीं थी। पुराने जिलों की बहाली से विवादित क्षेत्रों में शांति और संतुलन लाना। भाजपा ने इसे कांग्रेस के फैसलों को "अस्थिर और अव्यवस्थित" दिखाने का मौका बनाया। यह कदम भाजपा के लिए यह संदेश देने का जरिया हो सकता है कि वह "जिम्मेदार प्रशासन" देने में सक्षम है। कांग्रेस के वोट बैंक को कमजोर करना और अपने समर्थकों को यह दिखाना कि भाजपा निर्णयों को "आर्थिक और प्रशासनिक विवेक" के आधार पर लेती है। आगामी चुनावों के मद्देनजर भाजपा ने यह कदम उठाया, ताकि वह कांग्रेस के "अव्यावहारिक" फैसले को जनता के सामने उजागर कर सके।

परिणाम कुछ भी संभव

भाजपा सरकार को इस कदम के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यदि सरकार इस कदम के बाद प्रभावी प्रशासन, संसाधनों का सही उपयोग, और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित कर पाती है, तो यह निर्णय उसके व प्रदेश के लिए लाभकारी हो सकता है। लेकिन, अगर जनता को लगा कि उनकी समस्याओं की अनदेखी की गई है, तो यह कदम राजनीतिक दृष्टि से नुकसान का कारण बन सकता है। सरकार के लिए असंतोष वाले क्षेत्रों को संभालना और यह सुनिश्चित करना कि बड़े जिलों के पुनर्गठन से प्रशासनिक और विकासात्मक लाभ जनता तक पहुंचें, बड़ी चुनौती होगी।

प्रतिकूल व अनुकूल, दोनों परिणाम संभव

जिलों की संख्या कम करने के कदम पर जनता क्या सोचती है, ये तो भविष्य के गर्भ में है और आगामी चुनाव में ही पता चलेगा। इस निर्णय से सरकार को सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों प्रकार के परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ये मान सकते हैं कि जिलों की संख्या घटाने से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी। छोटे जिलों के कारण बढ़े खर्च को नियंत्रित करके सरकार उन संसाधनों का उपयोग अन्य विकास कार्यों में करेगी। जिन क्षेत्रों में नए जिलों के निर्माण से असंतोष था, वहां यह कदम एक समाधान के रूप में देखा जा सकता है। वहीं जिन क्षेत्रों का जिला मुख्यालय हटाया गया है या जिन जिलों को पुनः बड़े जिलों में मिलाया गया है, वहां के लोगों को यह महसूस हो सकता है कि उनका क्षेत्र विकास से वंचित हो जाएगा। प्रभावित क्षेत्रों में लोग इस कदम को "राजनीतिक निर्णय" मानकर भाजपा के खिलाफ नाराजगी प्रकट कर सकते हैं। छोटे जिलों के कारण जिन लोगों को स्थानीय स्तर पर सुविधाएं मिलने लगी थीं, वे अब पुनः बड़ी दूरी तय करने को मजबूर हो सकते हैं। ये तो भविष्य में प्रदेश के विकास से ही पता चल पाएगा कि भाजपा सरकार का ये फैसला गलत था या सही।

विष्णुदेव साय सरकार का एक साल

उपलब्धियां कई और चुनौतियां भी कम नहीं

राजेश लाहोटी ✍
वरिष्ठ पत्रकार

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने अपने पहले एक साल में कई महत्वपूर्ण और प्रभावशाली फैसले लिए हैं। इस अवधि के दौरान, सरकार ने विभिन्न पहलें की हैं जिनमें किसानों को समर्थन मूल्य पर धान की खरीद, महतारी वंदन योजना, पीएम आवास योजना, और विशेषकर बस्तर क्षेत्र के विकास के लिए उठाए गए कदम शामिल हैं। इन निर्णयों ने छत्तीसगढ़ के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है।

नक्सल समस्या समाधान का प्रयास

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार की एक प्रमुख उपलब्धि नक्सल समस्या के समाधान में देखी जा सकती है।

बस्तर क्षेत्र, जो लंबे समय से नक्सलवाद की चपेट में था, अब सुरक्षा और विकास के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव महसूस कर रहा है। साय सरकार ने इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं, जिससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास की स्थिति में सुधार हुआ है। यह सरकार की एक बड़ी सफलता है और नक्सल समस्या का समाधान राज्य की स्थिरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।

नागरिक समस्याओं के समाधान में देरी... हालांकि, नई सरकार में अफसरशाही की कार्यशैली में अभी भी कांग्रेस शासनकाल की तरह की समस्याएं देखी जा रही हैं। लापरवाही, भ्रष्टाचार और नागरिक समस्याओं के समाधान में देरी जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। इसके अलावा, कर्मचारियों के बीच असंतोष दूर करने में भी सरकार सुस्त नजर आ रही है।

कई मुद्दों पर अब तक ठोस समाधान नहीं

संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का वादा, और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण जैसे मुद्दों पर मुख्यमंत्री साय की सरकार ने अभी तक ठोस समाधान नहीं निकाला है। युवाओं को रोजगार देने के वादे भी पूरे नहीं हुए हैं, और पुलिस एसआई भर्ती के परिणाम का भी अब तक इंतजार है। इन मुद्दों के चलते, सरकार की कार्यक्षमता और प्रभावशीलता पर नागरिकों की संतुष्टि का स्तर कितना रहेगा, यह भविष्य में देखा जाएगा।

- इस एक साल में लगभग 3 महीने का समय लोकसभा चुनावों में व्यतीत हुआ है, जो सरकार के कार्यकाल पर असर डालने वाला एक महत्वपूर्ण कारक था। हालांकि चुनावी व्यस्तताओं और समय की सीमाओं के बावजूद, साय सरकार ने अपनी योजनाओं और नीतियों के माध्यम से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

- सुशासन के सिद्धांतों को लागू करने में साय सरकार ने प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया है। ई-फाइलिंग और भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई जैसे प्रयासों ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा, सरकार ने भूमि विवादों को कम करने और किसानों को राहत देने के लिए तहसीलदारों को अधिक अधिकार सौंपे हैं, जिससे भूमि विवादों के समाधान में तेजी आई है और किसानों को न्याय मिल पा रहा है।

- कुल मिलाकर, साय सरकार ने अपने 8 माह के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण और प्रभावी कदम उठाए हैं। समय की सीमाओं और चुनावी व्यस्तताओं के बावजूद, सरकार ने प्रभावी नीतियों और योजनाओं को लागू करके छत्तीसगढ़ में विकास की गति को तेज किया है और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में योगदान किया है। हालांकि, युवाओं को रोजगार देने के वादों और अन्य समस्याओं के समाधान की दिशा में भविष्य में सरकार की कोशिश ही उसकी सफलता में गिनी जाएगी।

वन नेशन वन इलेक्शन दूर की कौड़ी, भाजपा की सत्ता में ही बनेगी बात

इस मामले को लेकर गठित जेपीसी की पहली बैठक 8 जनवरी को संपन्न हो गई। जिसमें प्रत्येक सदस्य को 18000 पन्नों की रिपोर्ट दी गई है। जिसे पढ़कर वे आगे सवाल जवाब करेंगे ।

दिनेश रामावत ✍
वरिष्ठ पत्रकार

वन नेशन वन इलेक्शन का नारा सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जितना सरल बोलने में उतना ही दुभर है इसका क्रियान्वयन। मोदी सरकार ने संसद में इस बिल को स्वीकार कर जेपीसी को सौंप दिया है। जेपीसी के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी कह चुके हैं कि 2029 में जब नई संसद का चुनाव होगा तब राष्ट्रपति अगली सांसदी यानी 2034 में संसद के चुनाव और विधानसभा के चुनाव साथ करवाने के लिए कैलेंडर जारी करेंगे। यानी करीब 9 साल का समय इस व्यवस्था को लागू करने में लगेगा। अब अगर 2029 में भी नरेंद्र मोदी प्रधान मंत्री बनें या भाजपा की सरकार लगातार चौथी बार बनी तो यह सम्भव होगा, यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो यह बहुत दूर कौड़ी है। अभी हम 2025 में आए हैं, 2034 गंगा में बहुत सा पानी बह जाएगा। अचरज इस बात का है कि भाजपा ने जब इसका राग 2014 में छेड़ा था तो बिल 2024 में क्यों लाई ? भाजपा की पहली दो सरकारें संसद में ज्यादा मजबूत थी। शायद इसका सही और सटीक जवाब समय के चलती राजनीति से सामने आएगा। लेकिन इतना तय है कि इसे लागू करवाने के लिए भाजपा को अपने सहयोगियों को भी मनाना पड़ेगा जो इतना आसान नहीं है। इसके लिए संसद में संविधान संशोधन करवाने होंगे। विपक्ष पहले ही इस कानून के विरोध में है और 240 सदस्यों के साथ सत्ता में मौजूद भाजपा के लिए अपने सहयोगियों को भी इसके लिए राजी करना आसान नहीं है।

पीपी चौधरी ने बैठक के बाद कहा... 39 सदस्यों में से 37 सदस्य की मौजूदगी बताती है कि **सभी इस विषय को लेकर गंभीर**

इस बीच संसद की संयुक्त समिति की बैठक 8 जनवरी को पी पी चौधरी की अध्यक्षता में हो गई। पी पी चौधरी ने बैठक के बाद कहा था कि 39 सदस्यों में से 37 सदस्य की मौजूदगी बताती है कि सभी सदस्य इस विषय को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने अपने अपने सवाल भी किए। हमें उम्मीद है कि सब मिलकर इस पर काम करेंगे। इस पहली बैठक में प्रत्येक सदस्य को कोविद कमेटी की 18 हजार पन्नों की रिपोर्ट सौंपी गई। बैठक में एक साथ चुनाव करवाने से खर्चा बचने की बात पर विपक्षी सांसदों द्वारा पूछा गया कि इसके लिए कितनी ईवीएम की जरूरत पड़ेगी ? बचत कितनी होगी ? इस मुद्दे को कांग्रेस सांसद और समिति की सदस्य प्रियंका गांधी वडेरा पहले भी उठा चुकी है। बैठक में दिए गए दस्तावेजों का समिति के सदस्य अध्ययन करेंगे और उसके बाद अगली बैठकें आयोजित होगी।

यहां यह बात भी दिगर है कि वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चाओं के बीच देश में जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव भी एक साथ नहीं हुए थे। इसको लेकर विपक्ष ने सरकार को निशाने पर लिया था। अब लोकसभा के 27 और राज्य सभा के 12 सांसदों के साथ गठित ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस बिल पर चर्चा करने के लिए बनाई है। जिसके अध्यक्ष पाली सांसद पी पी चौधरी है, उन्होंने इस पर मंथन शुरू किया है।

देश का सबसे पहला आम चुनाव 10 करोड़ रुपए में हुआ
वर्ष 2024 में 1,00,000 करोड़ से अधिक खर्च हुए

हालांकि पी पी चौधरी अध्यक्ष बनने के बाद कह चुके है कि इस बिल को लागू करवाने के लिए वे इससे जुड़े सभी हितधारकों से बात करेंगे। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती जेपीसी ही है जिसमें विपक्ष के नेता शामिल है और उनको इसके लिए राजी करना होगा। यह होने पर ही आगे बात बनेगी। बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाना होगा। कोविंद कमेटी सिफारिशों में भारत में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' को लागू करने के लिए दो बड़े संविधान संशोधन करने होंगे। इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन करना पड़ेगा।

इसके बाद फिर राज्यों का रुख होगा।

बहरहाल पी पी चौधरी वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे जरूर गिनाने लगे हैं। वह कहते हैं कि इससे चुनाव का खर्चा बचेगा, बार-बार आचार संहिता नहीं लगेगी, विकास के कार्य नहीं रुकेंगे। इतना ही नहीं वे कोविंद कमेटी की सिफारिश के अनुसार लोकसभा विधानसभा के एक साथ चुनाव के बाद पूरे देश में अगले 100 दिनों में स्थानीय निकाय के चुनाव अभी एक साथ करवाने के लिए भी मेकैनिज्म बनाने की बात कर रहे हैं।

अगर 2029 तक सांसद में यह बिल पारित होता है तो संसद के चुनाव के बाद राष्ट्रपति अगले चुनाव के लिए जो कलैंडर जारी करेंगे उससे उन्हें कई राज्यों के विधानसभा कार्यकाल में बदलाव करना पड़ेगा। 2034 के लोकसभा चुनाव व विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने के लिए उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब के राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 3 से 5 महीने घटना पड़ेगा। जबकि गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल, मेघालय, नगालैंड, जैसे राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 13 माह से ज्यादा कम करना पड़ेगा। इसके लिए तब की राजनीतिक परिस्थितियां भी बेहद मत्वपूर्ण होगी।

मसलन खास तौर से क्या भाजपा अगले दस साल तक केंद्र में रहेगी? उसके सहयोगी दल क्या अपेक्षा रखेंगे? अगर भाजपा की सरकार 2029 में नहीं आई तो क्या होगा? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं हैं। लेकिन इतना तय है कि देश में पहले आम चुनाव जहां सिर्फ 10 करोड़ रुपए में हो गए थे । सेंटर फॉर मीडिया के अध्ययन के मुताबिक 2024 के आम चुनाव में, पिछले चुनाव की तुलना में लगभग दोगुना यानी, 1,00,000 करोड़ से अधिक रुपये खर्च हुए हैं। यह भारत में महंगे होते चुनाव को दर्शाता है।

पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव-2025 विशेष

जोधपुर में हस्तशिल्प उत्सव का मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किया शुभारंभ

राजस्थान का हस्तशिल्प प्रदेश का गौरव, हस्तशिल्प में प्रगति के नए रास्ते खोल रही राज्य सरकार, पीएम कुसुम योजना में पिछली सरकार की तुलना में 31 गुना अधिक काम **-मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा**

राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान का हस्तशिल्प प्रदेश का गौरव है। यह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई और प्रभावी नीतियां तैयार की हैं तथा स्टार्टअप क्षेत्र में भी नवाचार को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि हस्तशिल्प के संरक्षण एवं संवर्धन से विकसित राजस्थान और आपणो अग्रणी राजस्थान का विजन साकार रूप लेगा। श्री शर्मा को जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस उत्सव के माध्यम से प्रदेश के हस्तशिल्प को बढ़ावा के साथ ही कारीगरों के लिए भी समृद्धि एवं रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। राज्य की ब्लू पॉटरी, मार्बल के हस्तशिल्प, पीतल की कलाकृतियां, मिनिएचर पेंटिंग, काष्ठ कलाकृतियां, कपड़ा छपाई आदि दुनियाभर में प्रसिद्ध हैं। ऐसे में यह उत्सव प्रदेश की अद्भुत हस्तशिल्प कला के संरक्षण एवं संवर्धन का एक सशक्त मंच प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस उत्सव में राइजिंग राजस्थान के प्रयासों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

प्रदेश में पीएम कुसुम योजना को मिल रही गति

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कार्यकाल के पहले वर्ष में प्रदेश के विकास के लिए पानी-बिजली को केन्द्र मानते हुए कार्य किया। प्रदेश में जल उपलब्धता की आवश्यकता को ध्यान में रखकर संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना का मार्ग प्रशस्त किया एवं प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में 2 लाख 24 हजार करोड़ रुपये के एमओयू किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में पीएम कुसुम योजना को गति मिल रही है और प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में इस योजनान्तर्गत हमारी सरकार ने 31 गुना अधिक काम किया है।

हस्तशिल्प का उत्थान राज्य सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 6 लाख से ज्यादा शिल्पकारों और कारीगरों के लिए हस्तशिल्प के क्षेत्र में प्रगति के नए रास्ते खोले जा रहे हैं। सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं, जिनमें कारीगरों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर प्रशिक्षण और विपणन जैसे अवसर प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के शिल्पकारों और कारीगरों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने के लिए कौशल विकास को बढ़ावा दे रही है। हाल ही में राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 और एक जिला, एक उत्पाद (ओडीओपी) नीति जैसी पहल की गई हैं। जिलों की उत्कृष्ट हस्तशिल्प को ओडीओपी में शामिल कर विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

20 फीट की शिव प्रतिमा आकर्षण का केंद्र... भारतीय सभ्यता और संस्कृति से ओतप्रोत इस मेले में आने वाले लाखों लोगों के लिए 20 फुट की विशेष शिव प्रतिमा भी सेंट्रल पंडाल के बाहर लगाई गई। इस शिव प्रतिमा ने हर किसी का ध्यान अपनी और आकर्षित किया और मेले में आने वाले लोगों ने यहां खूब सेल्फी ली।

पीएम विश्वकर्मा योजना से आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम

श्री शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के हस्तशिल्पियों और कलाकारों की कला को सम्मानित करने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरूआत की है। इस योजना में राज्य सरकार द्वारा 2 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान जारी कर उन्हें सक्षम एवं समृद्ध बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से कलाकारों को उचित प्रशिक्षण, ऋण सहायता और वैश्विक बाजार तक पहुंच मिल रही है जिससे वे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभा सकें।

हस्तशिल्प, हैंडलूम और एमएसएमई के 50 नए क्लस्टर किए जाएंगे विकसित

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदर्शनी, कार्यशाला, सेमिनार आदि के आयोजन के लिए जयपुर में पीएम यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। साथ ही, प्रदेश में हस्तशिल्प, हैंडलूम और एमएसएमई के 50 नए क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि माटी कला से जुड़े प्रदेश के कलाकारों के उत्थान के लिए माटी कला उत्कृष्टता केंद्र, चयनित खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं एवं समितियों के साथ ही बुनकर संघ से जुड़े बुनकरों को ऋण एवं सहायता उपलब्ध करवाना, नई पर्यटन इकाई नीति जैसे निर्णयों से हमारे शिल्पकारों को बढ़ावा मिलेगा।

हस्तशिल्प में नवाचार और तकनीक का हो रहा समावेश

श्री शर्मा ने कहा कि हम पारंपरिक हस्तशिल्प कला को संरक्षित करने के साथ इसे नवाचार और आधुनिक तकनीक से जोड़कर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी उत्कृष्ट बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री 4.0 की ओर बढ़ने में हस्तशिल्प को तकनीकी नवाचार और स्मार्ट समाधानों का हिस्सा बनाना जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा शिल्पकारों को भी स्मार्ट टेक्नोलॉजी एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है।

इससे पहले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दीप प्रज्वलन कर हस्तशिल्प उत्सव का विधिवत शुभारंभ किया एवं उत्सव के केन्द्रीय पांडाल एवं बेट द्वारका का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 'लूणीः समग्र विकास को समर्पित एक वर्ष' विकास पुस्तिका, मसाला उद्योग से संबंधित फोल्डर एवं लघु उद्योग भारती के मुख पत्र लघु उद्योग टाइम्स का भी विमोचन किया। साथ ही, मुख्यमंत्री ने 5 पाक विस्थापितों को पट्टे भी वितरित किए।

कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल, उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री श्री के.के. बिश्नोई, जीव जंतु कल्याण बोर्ड अध्यक्ष श्री जसवंत सिंह विश्नोई, राज्यसभा सांसद श्री राजेंद्र गहलोत, विधायक श्री देवेन्द्र जोशी, श्री अतुल भंसाली, श्री बाबूसिंह राठौड़, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक श्री निंबाराम, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री घनश्याम ओझा, लघु उद्योग भारती के संगठन मंत्री श्री प्रकाश चंद, प्रदेश लघु उद्योग भारती प्रदेश अध्यक्ष शांतिलाल बालड, लघु उद्योग भारती प्रांत अध्यक्ष महावीर चोपड़ा, प्रदेश संयुक्त महासचिव सुरेश बिश्नोई, बिंदु जैन, प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल, प्रदेश संगठन महासचिव मंजू सारस्वत, प्रांत उपाध्यक्ष भोजराज सारस्वत, प्रांत उपाध्यक्ष दीपक माथुर, प्रांत कोषाध्यक्ष नितिन सालेचा, राजेंद्र राठी, सुधींद्र दुग्गड, मनीष माहेश्वरी, गौतम जीरावाला , नितिन सालेचा, रवि गुप्ता, पंकज भंडारी, राजेंद्र सालेचा, थानाराम, पूनम तंवर, दिनेश सोनी, हरीश लोहिया, देवेंद्र डागा, प्रकाश जीरावाला, नितेश बूब, मोना हरवानी, कंचन लोहिया, किशनलाल गर्ग, जितेन्द्र माहेश्वरी, हंसराज बाहेती, अशोक बाहेती, अशोक संचेती, कृष्ण कुमार, जसराज बोथरा, ज्ञानीराम मालू, गौतम सालेचा, जीएम सिंघवी, सहित अन्य जनप्रतिनिधि व आमजन उपस्थित रहे।

हस्तशिल्प उत्सव ने हर वर्ग को किया आकर्षित

पश्चिम राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव-2.025 की मेला आयोजन नोडल एजेंसी लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने बताया कि इस बार हमारा प्रयास रहा कि इस मेले में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। मेले में प्रतिदिन महिलाओं, युवाओं और बच्चों के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

प्रत्येक दिन सजी सांस्कृतिक शाम... पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव-2025 में आमजन के आकर्षण के लिए प्रतिदिन शाम को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। खास बात ये कि सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम भारतीय सभ्यता और संस्कृति से ओतप्रोत रहे। लघु उद्योग भारती के जोधपुर प्रांत अध्यक्ष और मेला समन्वयक महावीर चोपड़ा ने बताया कि मेले में इन कार्यक्रमों ने नई ऊंचाइयां प्रदान की।

उद्योगों की समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर सेमीनार... हस्तशिल्प उत्सव में एग्री बिजनेस, सीएसआईआर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिजिटल डिटॉक्स और साइबर अवेयरनेस, सहकारिता, बिजकिड्स 'ए जर्नी टुवड्र्स बीइंग एंटरप्रेन्योर', पॉल्यूशन कंट्रोल, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, डायरेक्ट टैक्स पर हुई सेमिनार में विषय विशेषज्ञों ने अपने सारगर्भित व्याख्यान से महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की।

मेले में 700 से अधिक स्टॉल्स के लिए बनाए गए 15 डोम पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव-2025 में कुल 15 अलग-अलग डोम बनाए गए और लगभग 714 स्टॉल्स तैयार की गईं।

भेंट द्वारका थीम पर तैयार डोम में भेंट द्वारका के दर्शन

लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुख्य संयोजक घनश्याम ओझा बताया कि इस बार मेले में भेंट द्वारका थीम पर 80 गुणा 170 का विशेष डोम तैयार करवाया गया। इस डोम में भेंट द्वारिका के मार्ग की ही तरह सुरंग तैयार की गई और उसमे भेंट द्वारकाधीश का मंदिर भी बनाया गया। इस टनल में प्रवेश करने के साथ ही हर किसी को यह अहसास हुआ कि वह भेंट द्वारका की ही यात्रा कर रहा है और इस टनल में समुद्री जीव, वनस्पतियों का भी जीवंत प्रदर्शन किया गया।

सेंट्रल पांडाल में करीब 30 फीट की सरदार वल्लभभाई पटेल की 'स्टेच्यू ऑफ यूनिटी' प्रतिमा बनी आकर्षण का केन्द्र... पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव-2025 के मेला समन्वयक महावीर चोपड़ा ने बताया कि यह वर्ष सरदार पटेल वल्लभभाई पटेल का 150वां जयंती वर्ष है और केंद्र सरकार ने 2 वर्ष तक जन्म शताब्दी महोत्सव बनाने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में देश को एक और अखंड बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने वाले सरदार वल्लभभाई पटेल की 30 फीट की 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' स्थापित की गई। जो उत्सव में आकर्षण का केन्द्र रही।

मारवाड़ की कला, साहित्य, संस्कृति व विरासत के संरक्षक महाराजा गज सिंह

राजेंद्र सिंह लीलियां
जनसंपर्क अधिकारी,
उम्मेद भवन पैलेस

जोधपुर के महाराजा गज सिंह मारवाड़ की कला, साहित्य, संस्कृति एवं विरासत के संरक्षक के रूप में अपनी बेहतरीन भूमिका हमेशा से ही निभा रहे हैं। आपकी भूमिका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मारवाड़ के सांस्कृतिक दूत की है। महाराजा गज सिंह देश व विदेश मे लोकप्रिय व्यक्तियों में गिने जाते हैं। देश के पूर्व राज परिवारों में आपकी अच्छी छवि मानी जाती है। लोगों से आपका गहरा जुड़ाव व अपनापन है।

मारवाड़ की जनता से अपणायत के रिश्ते

देश में प्रजातंत्र के बाद में भी जोधपुर के राज परिवार व महाराजा गज सिंह के प्रति मारवाड़ की सभी जाति, धर्म, समाज के लोगों में बहुत सम्मान है। मारवाड़ की जनता के साथ आपके अपणायत भरे रिश्ते हैं। आपका हर समाज के साथ गहरा जुड़ाव है। सभी धर्म व समाज के समारोह में आप शिरकत करते हैं। महाराजा गज सिंह हमेशा कहते हैं कि मेरी पहचान मारवाड़ की जनता से है। ''म्हारी ओलखाण आपसूं'' है।

राजदादीसा व राजमातासा के संस्कार

महाराजा गज सिंह का जन्म 13 जनवरी 1948 को हुआ। इनके जन्म के 4 वर्ष बाद पिता महाराजा हनवन्त सिंह का 26 जनवरी 1952 को विमान दुर्घटना में निधन हो गया। यह समय जोधपुर राज परिवार के लिए अनुकूल नहीं था। युवराज गज सिंह का 12 मई 1952 को महाराजा के रूप में राजतिलक हुआ। ऐसे समय में स्वर्गीय महाराजा उम्मेद सिंह की धर्मपत्नी राजदादीसा बदन कंवर ने इस विकट समय में राजपरिवार के संरक्षक की बेहतर भूमिका निभाते हुए परिस्थितियों को सही तरह से संभाला एवं स्वर्गीय महाराजा हनवन्त सिंह की धर्मपत्नी राजमाता कृष्णा कुमारी ने महाराजा गज सिंह का राजसी परम्परानुसार बेहतर लालन-पालन किया व संस्कारवान बनाया।

विदेश में उच्च शिक्षा, पर संस्कार भारतीय

महाराजा गज सिंह ने इंग्लैंड में कोटहिल हाउस ईटन कॉलेज व क्राइस्टचर्च ऑक्सफोर्ड से 1970 में उच्च शिक्षा प्राप्त की। राजनीति, अर्थशास्त्र व दर्शन शास्त्र में ग्रेजुएशन (ऑनर्स) और एम. ए किया। विदेश में पढ़ाई के बावजूद भी अपने संस्कार कायम रखे।

विदेश से लौटने पर हुआ ऐतिहासिक स्वागत... महाराजा गज सिंह के विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त कर जोधपुर आने पर 11 नवंबर 1970 को रेलवे स्टेशन से मेहरानगढ़ में मां चामुंडा मंदिर में दर्शन कर उम्मेद भवन पैलेस पहुंचने तक मारवाड़ की जनता ने जगह-जगह ऐतिहासिक स्वागत किया।

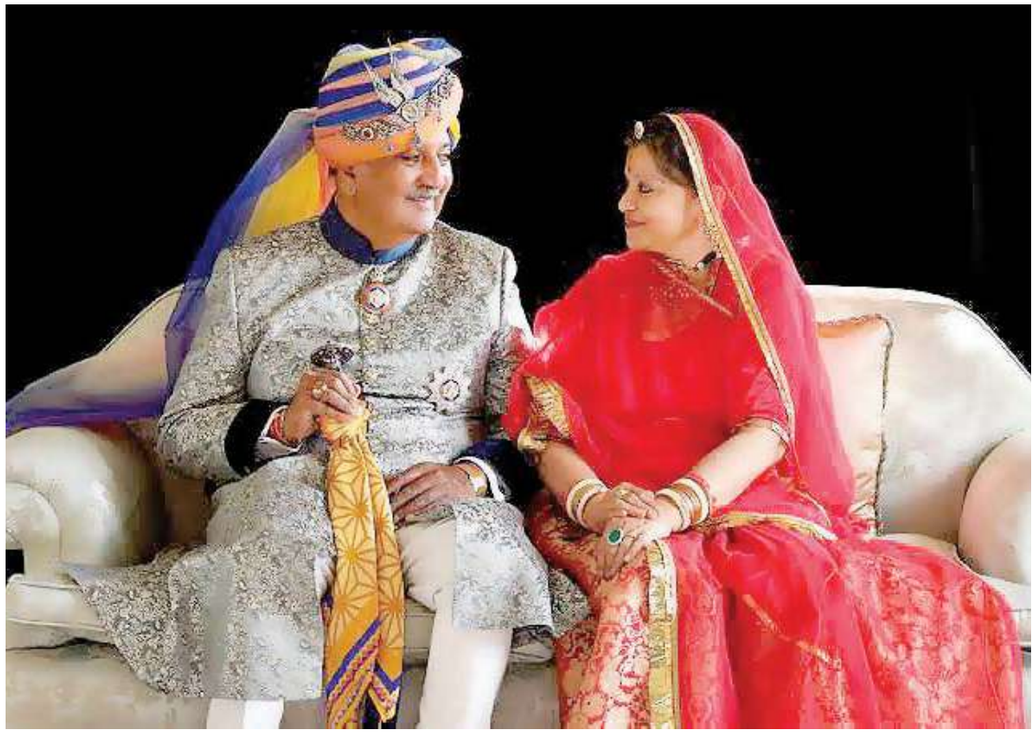

महारानी हेमलता राज्ये का बेहतरीन साथ... महाराजा गज सिंह का विवाह 19 फरवरी 1973 को पुंछ राज परिवार में राजा शिवरतन सिंह देव की पुत्री राजकुमारी हेमलता राज्ये के साथ संपन्न हुआ। हमेशा अपनापन, सजग व सक्रिय एवं लोगों से सीधे जुड़ाव रखने वाली महारानी हेमलता राज्ये जीवन संगिनी के रूप में महाराजा गज सिंह के हर कार्य, विचार व सोच में पूरा सहयोग रखती है। उनके हौसलों व इरादों को मजबूती प्रदान करती है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक दूत की भूमिका

महाराजा गज सिंह देश-विदेश में अपने मारवाड़ व जोधपुर की कला, संस्कृति, पर्यटन, विरासत की पहचान बनाने में सांस्कृतिक दूत की भूमिका निभा रहे हैं।

कला व संस्कृति एवं इतिहास संरक्षण के आयोजन... महाराजा गज सिंह के मुख्य संरक्षण में कला व संस्कृति को बढ़ावा देने व इतिहास संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान के लोक कलाकारों को नई पहचान दिलाने के लिए मेहरानगढ़ फोर्ट में प्रतिवर्ष सूफी फेस्टिवल व जोधपुर रिफ जैसे बड़े आयोजन करवाए जाते हैं, जिसमें स्थानीय व देशी-विदेशी कलाकारों को एक मंच मिलता है। इसके साथ ही मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट व महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश केन्द्र द्वारा अनेक अंतरराष्ट्रीय-राष्ट्रीय संगोष्ठियों व समारोहो का आयोजन व पुस्तकों का प्रकाशन व शोध कार्य हो रहा है।

मारवाड़ की प्रतिभाओं का संरक्षण व सम्मान

प्रत्येक वर्ष 12 मई को जोधपुर स्थापना दिवस समारोह में मारवाड़ की विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली प्रतिभाओं को मेहरानगढ़ दुर्ग में मारवाड़ रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाता है। वीर दुर्गादास राठौड़ जयंती समारोह पर भी मारवाड़ की प्रतिभाओं का सम्मान किया जाता है। उम्मेद भवन पैलेस मे तिथि के अनुसार आयोजित जन्मदिन पर परंपरा अनुसार सम्मान प्रदान किए जाते हैं।

अनेक संस्थाओं को मिल रहा है संरक्षण

महाराजा गज सिंह अनेक संस्थाओं, संगठनों, ट्रस्टों, चैरिटेबल ट्रस्टों के मुख्य संरक्षक व अध्यक्ष के पदों पर पदस्थापित हैं। देशभर में अनेक संस्थाओं के चेयरमैन हैं। इन संस्थाओं को अपनी कार्यशैली व व्यक्तित्व से आगे बढ़ाने की प्रभावी भूमिका में रहते हैं।

बालिका शिक्षा को बढावा... बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महाराजा गज सिंह द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जोधपुर में राजमाता कृष्णा कुमारी गर्ल्स पब्लिक स्कूल की स्थापना की, जिसका स्थान देश के बेहतरीन गर्ल्स स्कूलों में है। इसके साथ ही पाली जिले के देसूरी फोर्ट में हिज हाइनेस महाराजा हनवन्त सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में 1987 से राजमाता कृष्णा कुमारी गर्ल्स हॉस्टल संचालित हो रहा है। केरू फोर्ट में भी मोहन कंवर गर्ल्स हॉस्टल संचालित किया जा रहा है।

राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए निरंतर प्रयासरत

महाराजा गज सिंह वर्षों से राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए लगातार हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। केंद्र व राज्य सरकार के स्तर पर निरन्तर प्रयासरत हैं। नई दिल्ली के बोट क्लब पर भी आपकी अगुवाई में धरना दिया गया था।

मारवाड़ में जल संरक्षण व जल संचय के लिए सार्थक प्रयास... मारवाड़ में निरंतर पड़ते अकाल और सूखे व कम वर्षा की स्थिति को देखते हुए लोगों में जल संरक्षण व जल संचय के प्रति जागरूकता के लिए आपने जल भागीरथी फाउंडेशन की स्थापना कर मारवाड़ के अनेक स्थानों में जल संरक्षण के कार्य करवाए व लोगों को जल संचय के प्रति भी जागरूक करने का कार्य करवा रहे हैं।

अनेक उच्च पदों पर बेहतर कार्य किया

महाराजा गज सिंह ने जिस पद पर भी कार्य किया, अपनी प्रभावी छाप छोड़ी। 1971 से 1980 तक वेस्टइंडीज के ट्रिनिडाड व टोबगो में भारतीय उच्चायुक्त रहे, यह समय याद करने योग्य है। 22 मार्च 1990 से 4 जून 1992 तक राज्यसभा में निर्दलीय व निर्विरोध सांसद रहते हुए संसद में अपनी अलग पहचान बनाई। 1994 से 1998 तक आर टी डी सी के चेयरमैन रहते हुए राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण कार्य किया।

मारवाड़ में वर्षा के लिए रामदेवरा पदयात्रा... महाराजा गज सिंह ने मारवाड़ के लोगों की सुख समृद्धि व अकाल की स्थिति में वर्षा के लिए 5 सितंबर 1986 को जोधपुर से रामदेवरा तक पदयात्रा की व लोक देवता बाबा रामदेव जी के दर्शन कर प्रार्थना की। इस पदयात्रा में जोधपुर से अनेक लोग आपके साथ थे व रास्ते में अनेक लोग जुड़ते गए। जगह-जगह पदयात्रा का स्वागत हुआ।

अंतरराष्ट्रीय अवार्ड

वर्ल्ड मोन्यूमेट फंड न्यूयॉर्क ने मानवता की कलात्मक व सांस्कृतिक पुरातात्विक संपदा के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च कोटि का नेतृत्व प्रदान करने के लिए 27 अक्टूबर 2006 में हेंड्रियन अवार्ड, 2011 में इटोज हॉल ऑफ फेम अवार्ड, 25 नवंबर 2014 को नई दिल्ली में कला, पर्यटन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोनडे नास्ट ट्रैवलर द्वारा लाइव टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। आपके संरक्षण में मेहरानगढ़ दुर्ग को यूनेस्को एशिया पेसिफिक अवार्ड, 2013 में नागौर दुर्ग को आगा खान अवार्ड फॉर आर्किटेक्चर के लिए नामित किया गया।

पोलो को नई पहचान व संरक्षण... जोधपुर व पोलो का लंबा इतिहास रहा है। रियासत काल में पोलो खिलाड़ी विदेश में भी पोलो खेलते थे। महाराजा गज सिंह ने पोलो को नई पहचान व संरक्षण देते हुए 1998 में जोधपुर पोलो एंड इक्वेस्ट्रियन इंस्टिट्यूट की स्थापना करके महाराजा गज सिंह स्पोर्टस फाऊंडेशन पोलो मैदान में घास का मैदान तैयार करवाया व हर वर्ष दिसम्बर में पोलो सीजन का आयोजन करवाते हैं, इसमें देश-विदेश से प्रसिद्ध खिलाड़ी खेलने आते हैं। स्थानीय खिलाड़ियों को भी उनके साथ खेलने का मौका मिलता है। आपके पुत्र युवराज शिवराज सिंह भी पोलो के अंतरराष्ट्रीय स्तर के बेहतरीन खिलाड़ी रहे। इन्होंने भी पोलो को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन कार्य किया है।

जोधपुर पोलो का 147 वर्ष का स्वर्णिम इतिहास

जोधपुर पोलो का लंबा इतिहास रहा है। जोधपुर के पोलो खिलाड़ियों ने पोलो मैच खेलते हुए दुनिया में अपनी अलग पहचान बनायी है। पोलो का 147 वर्ष का स्वर्णिम इतिहास हमेशा याद रखा जायेगा। यहां के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पोलो खेलते हुए जोधपुर का नाम रोशन किया। आज भी जोधपुर में पोलो के अनेक बेहतरीन खिलाड़ी पोलो से जुड़े हुए हैं।

जोधपुर पोलो टीम इंग्लैंड में 1925 में (आई पी ए ट्रॉफी - 1924 के साथ) ठाकुर पृथ्वी सिंह बेड़ा, कैप्टन एएच विलियम्स, राव राजा हणूत सिंह व राम सिंह।

महाराजा उम्मेद सिंह जयपुर टीम के साथ- साथ में महाराज पृथ्वी सिंह , महाराजा सवाई मानसिंह जयपुर व राव राजा हणूत सिंह ।

अजय अस्थाना
वरिष्ठ पत्रकार

- *उम्मेद सिंह व सर प्रताप ने की जोधपुर में पोलो की शुरुआत*
- *1957 में फ्रांस में जीता वर्ल्ड कप*
- *जोधपुर के पोलो खिलाड़ियों ने विदेश में गहरी छाप छोड़ी*
- *जोधपुर पोलो के आधुनिक सफर का श्रेय महाराजा गज सिंह को*
- *जोधपुर में प्रति वर्ष महाराजा गज सिंह आयोजित करवाते पोलो सीजन*

जोधपुर में पोलो की शुरुआत . 1889 में हुई। जोधपुर पोलो टीम ने 1893 में अपनी पहली ट्रॉफी राजपूताना चैलेंज कप जीती , इस टीम में सर प्रताप, ठाकुर धौकल सिंह व कर्नल बिटसन थे। 1897 में जोधपुर टीम इंग्लैंड गई व हर्लिंगम व रानेलाघ में कई मैच जीते। महाराजा उम्मेदसिंह व सर प्रताप ने जोधपुर रियासत काल में 'जोधपुर लांसर्स' का गठन किया। सर प्रताप के खेल प्रेम के कारण पोलो के विकास में काफी मदद मिली। यहां कि टीम ने जहां देश में विभिन्न स्थानों पर अपने उत्कृष्ट खेल की छाप छोड़ी, वही खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें अलवर, किशनगढ़, भोपाल आदि रियासतों ने अपनी ओर से खेलने के लिए आमंत्रित किया। महाराजा उम्मेदसिंह व सर प्रताप द्वारा शुरु किए पोलो में रावराजा हणूतसिंह, महाराज प्रेमसिंह व कर्नल किशनसिंह ने अनेक देशों में पोलो खेलकर जोधपुर का नाम गौरवान्वित किया। उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन पर इन्हें खेलों के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान 'अर्जुन अवार्ड' से विभूषित किया गया था। रावराजा हणूतसिंह को 1958 में पद्मभूषण व 1964 में अर्जुन पुरस्कार, महाराज प्रेमसिंह को 1961 व कर्नल किशनसिंह को 1963 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया।

पटियाला को हराकर जोधपुर ऑल इंडिया चैंपियन बना

जोधपुर पोलो टीम - 1924... कोलकाता पोलो चैंपियनशिप कप विजय

जोधपुर पोलो टीम की शुरुआत में ठाकुर हरिसिंह (हरजी) व ठाकुर धोकलसिंह अच्छे खिलाड़ी माने जाते थे। हरजी ने 1887 से 1901 तक पोलो खेला। जनरल बीटसन की सलाह पर जोधपुर लांसर्स को आगे बढ़ाने में महत्ती भूमिका निभायी। उस समय सरप्रताप, हरजी, धोकलसिंह, जनरल बीटसन की पोलो टीम बेहतरीन मानी जाती थी। 1922 में ब्रिटेन के महाराजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स के सम्मान में दिल्ली में पटियाला व जोधपुर की टीमों के बीच मैच हुआ जिसमें जोधपुर की टीम ने रोमांचक मैच में पटियाला की टीम को हरा ऑल इंडिया चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया । इस टीम में ठाकुर पृथ्वी सिंह बेड़ा ,दलपत सिंह रोहित , राम सिंह व राव राजा हणूत सिंह शामिल थे । सितम्बर 1922 में सर प्रताप का निधन हो गया, लेकिन उन्होंने पोलो को जिन ऊँचाईयों पर पहुँचाया, वह ऊँचाईयाँ निरन्तर जारी रहीं।

विदेश में शानदार खेल खेला

1925 में महाराजा उम्मेदसिंह के नेतृत्व में पोलो टीम इंग्लैण्ड गई, वह अनेक प्रमुख टूर्नामेंट जीते । इस टीम में रावराजा हणूतसिंह, अभयसिंह, पृथ्वीसिंह, मेजर विलियम्स व रामसिंह शामिल थे। 1931 से 1939 तक भारतीय पोलो कप विजयी जयपुर टीम में जोधपुर के रावराजा हणूतसिंह व अभयसिंह शामिल थे। रावराजा हणूतसिंह ने 1933 में इंग्लैण्ड में जयपुर टीम में रहकर बेहतरीन प्रदर्शन किया। जोधपुर पोलो को बेहतर स्थान देने में 9 हैण्डीकेप के रावराजा हणूतसिंह का विशेष योगदान रहा है।

जोधपुर - जयपुर की संयुक्त टीम ने कई वर्षों तक विदेश में बेहतर खेल प्रदर्शन किया

▪ 1930 से 1933 भारतीय पोला का स्वर्णकाल

1930 में महाराजा उम्मेदसिंह के पोलो से रिटायर होने के बाद जोधपुर व जयपुर दोनों ने मिलकर पोलो टीम बनायी। दोनों की टीम ने मिलकर पोलो में वर्षों तक विदेशों में अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन से धाक जमाये रखी। 1933 में हार्लिंगटन ओपन, कोरोनेशन कप, इंडियन एम्पायर शील्ड, रोहेम्पना ओपन और रानले ओपन टूर्नामेंट में जीत हासिल की। यह समय भारतीय पोलो का स्वर्णकाल माना जाता था।

▪ फ्रांस में जीता वर्ल्ड कप

1957 में भारतीय टीम में रावराजा हणूतसिंह, कैप्टन विजयसिंह व कर्नल किशनसिंह ने जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह के साथ खेलते हुए फ्रांस के ज्यूविले में आयोजित विश्व कप जीत लिया। इन्होंने 1964 में इंग्लैण्ड में हुए अन्तर्राष्ट्रीय पोलो मैचों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इंग्लैण्ड की 14 स्पर्धाओं में से एक दर्जन बार उनकी टीम ने जीत का जश्न मनाया।

अमेरिका राष्ट्रीय ओपन पोलो... तब महाराज प्रेमसिंह ने पोलो में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया

अमेरिका की राष्ट्रीय ओपन पोलो में भी महाराज प्रेमसिंह ने भाग लेकर देश का नाम रोशन किया। 1961 में उन्होंने इंग्लैण्ड में खेलते हुए क्वीन्स कप प्रतियोगिता जीती। कोलकाता पोलो क्लब के शताब्दी वर्ष के दौरान 1961 में सेन्टेनरी कप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ब्रिगेडियर मसूद अली बेग, कर्नल सोढ़ी और कर्नल हार्पर के साथ खेलते हुए उन्होंने इस प्रतिष्ठित कप को जीतकर पुनः अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। 1937 से 1981 तक 45 वर्षों तक महाराज प्रेम सिंह ने शानदार पोलो का प्रदर्शन किया।महाराज प्रेमसिंह ने 1959 में इंग्लैण्ड में विश्व रिकॉर्ड बनाया, उन्होंने दो प्रहार में ही गोल कर दिया था। उनके प्रयासों से कोलकाता, मुंबई व चेन्नई में पोलो फिर से स्थापित हुआ। उन्होंने राष्ट्रीय आर्मी पोलो टीम को प्रशिक्षण भी दिया।

पोलो के प्रति उनके समर्पण और उपलब्धियों के लिए महाराज प्रेमसिंह को आजीवन भारतीय पोलो संघ का उपाध्यक्ष बनाया गया।

जोधपुर पोलो के आधुनिक सफर का श्रेय महाराजा गजसिंह को

जोधपुर पोलो के आधुनिक सफर की बात करते हैं तो इसको आगे बढ़ाने का पूरा श्रेय इण्डियन पोलो एसोसिएशन के उपाध्यक्ष महाराजा गजसिंह को जाता है। महाराजा के मुख्य संरक्षण में जोधपुर पोलो व इक्यूस्टेरियन इंस्टीट्यूट की स्थापना के साथ ही एयरपोर्ट के पाबूपुरा रोड़ पर मार्च 1998 में हरी घास युक्त महाराजा गजसिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो ग्राउंड की स्थापना की जाकर जोधपुर में पोलो सेशन की शुरुआत की। प्रति वर्ष एक माह चलने वाले पोलो सीजन में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पोलो खिलाड़ी पोलो खेलने आते हैं।

युवराज शिवराजसिंह ने पोलो को आगे बढ़ाने में भूमिका निभायी

महाराजा गजसिंह के पुत्र युवराज शिवराजसिंह जी ने भी पोलो को आगे बढ़ाने का बेहतर प्रयास किया। तीन हैण्डीकेप के युवराज शिवराजसिंह की गिनती देश के बेहतरीन पोलो खिलाड़ियों में रही है। देश व विदेश में अनेक टूर्नामेंट खेलकर इन्होंने जोधपुर पोलो की धाक बरकरार रखी। युवराज शिवराजसिंह, इंग्लैण्ड, केन्या, दक्षिणी अफ्रीका, मिश्र और फ्रांस सहित अन्य कई देशों में खेले। उन्होंने दिल्ली में सर प्रताप कप, जे एण्ड बी बड़ौदा कप, एस.एम. एस. गोल्ड कप भी जीता ।

जोधपुर के इन पोलो खिलाड़ियों ने भी अच्छा खेल खेला... जोधपुर के तीन हैडीकेप के आर के के वी सिंह , ठाकुर हर्षवर्धन सिंह भांवरी व एक हैडीकेप के ठाकुर दिग्विजय सिंह भांवरी व जैसल सिंह ने भी अपने समय में अच्छा पोलो खेला ।

देश के श्रेष्ठ खिलाड़ी खेल रहे हैं जोधपुर पोलो सीजन में... जोधपुर पोलो सीजन में 3 हैंडीकेप के जयपुर महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह , सैयद शमशिर अली, सिद्धांत शर्मा ,अभिमन्यु पाठक, सिमरन शेरगिल , 2 हैंडीकेप के अंगद कलान , ध्रुवपाल गोदारा, सहित अनेक बेहतरीन खिलाड़ी खेल रहे है।

विदेशी खिलाड़ी भी खेल रहे है... विदेशी खिलाड़ियों में 6 हैंडीकेप के सेंटीयागो माराम्बिओ , 5 हैंडीकेप के डेनियल ऑटोमेनडी, 4 हैंडीकेप के गोंजालो यानजोन, 4 हैंडीकेप के फेडेरिको बोउडो ,4 हैंडीकेप के लांस वाटसन भी खेल रहे हैं।

जोधपुर पोलो सीजन में जोधपुर के यह खिलाड़ी खेल रहे हैं...जोधपुर के योगेश्वरसिंह भांवरी, धनन्जयसिंह रावटी, विश्वराजसिंह भाटी, निखिलेन्द्रसिंह रावटी व भूमंज्य सिंह वर्तमान पोलो सीजन में खेल रहे हैं।

25 वें जोधपुर पोलो का आयोजन 30 दिसम्बर तक... जोधपुर में इस वर्ष 27 नवम्बर से 30 दिसम्बर 2025 तक 25 वें जोधपुर पोलो सीजन का आयोजन हुआ। महाराजा गज सिंह के संरक्षण में जोधपुर पोलो व इक्यूस्टेरियन इंस्टीट्यूट के सचिव इन्द्रजीत सिंह नाथावत अपनी टीम के साथ जोधपुर पोलो में बेहतर कार्य कर रहे है।

उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम

सभी पक्षों को सुप्रीम कोर्ट से आस

देवकीनंदन व्यास
अधिवक्ता, लेखक

भारत, एक ऐसा देश जो अपनी वैविध्यपूर्ण संस्कृति पर गौरव अनुभव करता है। अपने गैर-सांप्रदायिक संवैधानिक ढांचे के लिये दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों के बीच अपनी अलहदा पहचान रखने वाले इस देश में जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव को कोई जगह नहीं दी गई है। विविधता में एकता इस देश की पहचान है और इसीलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 यह प्रावधान करता है कि स्टेट यानी सरकार किसी भी व्यक्ति को कानूनी-समानता से इनकार नहीं करेगी और प्रत्येक व्यक्ति को भारत में कानून के समक्ष समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र में अब बहस का यह मुद्दा यह है कि जब भारत में जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक या आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता तो, फिर निश्चित ही इस देश में उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 को लागू किया जाना संविधान की मूल भावना के प्रतिकूल है।

राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिवक्ता दीपक बोड़ा उपासना स्थल अधिनियम की मुखालफत करते हुए कहते हैं कि यह कानून संविधान प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। बोड़ा भारतीय संविधान के प्रावधानों के हवाले से कहते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 और 16 धार्मिक और सामाजिक भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और धर्मनिरपेक्षता को संविधान के मूल सिद्धांत के रूप में स्थापित करता है। लेकिन, उपासना स्थल अधिनियम कुछ विशेष धार्मिक स्थलों को प्राथमिकता देता है, जो एक धर्म विशेष से संबंधित हैं और इसे अन्य धर्मों के अधिकारों के मुकाबले विशेष रूप से लागू करता है। बकौल बोड़ा- किसी भी देश को आक्रांताओं और लुटेरों की निशानियों पर गौरव नहीं हो सकता।

दरअसल, उपासना स्थल अधिनियम को 1991 में तब लागू किया गया था, जब केन्द्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली प्रधानमंत्री पी.वी नरसिंह राव की सरकार थी। 1991 का चुनाव मध्यावधि चुनाव था। 9वीं लोकसभा केवल 16 महीने में भंग हो गई थी और देश को फिर से 1991 में नए नेतृत्व का चयन करना पड़ रहा था। इसी साल अयोध्या में राममंदिर का मुद्दा भी प्रबल हो उठा था। 1991 के आम चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस ने सर्वाधिक 244 सीटें हासिल की। वहीं, भारतीय जनता पार्टी 120 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही।

इसी चुनाव से पूर्व मतदाताओं को रिझाने के लिए कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में धार्मिक स्थलों के रूपांतरण को रोकने के लिए कानून लाने का वादा किया। जून 1991 में सत्ता संभालने के बाद महज तीन महीने में 16 सितम्बर 1991 को कांग्रेस सरकार उपासना स्थल अधिनियम लेकर आ गई थी।

प्लेसेज ऑफ वर्शिप (स्पेशल प्रोविजन्स) एक्ट, 1991 के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। यानी यदि कोई स्थल मंदिर/मस्जिद आदि देश की आजादी के समय जिस किसी भी धर्म के पूजा स्थल के रूप पहचान रखता था, इस कानून के चलते उसे अब तोड़ा, ढहाया, गिराया या बदला नहीं जा सकता। अब वह हमेशा के लिए उसी धर्म का पूजा स्थल रहेगा। यदि कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना और तीन साल तक की जेल भी हो सकती है। कुल-मिलाकर इस कानून का उद्देश्य धार्मिक स्थलों के रूपांतरण को रोकना और 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्वरूप था, उसे बनाए रखने के लिए प्रावधान करना था।

भाजपा और अन्य विपक्षी दलों ने हालांकि इस कानून का पुरजोर विरोध किया, लेकिन आंकड़ों में कमजोर विपक्ष संसद में इस कानून को पारित होने से रोक न सका। चूंकि बाबरी मस्जिद व राम जन्मभूमि का विवाद 1947 से पहले से ही चल रहा था, लिहाजा बाबरी मस्जिद प्रकरण को इस नए कानून के दायरे से बाहर ही रखा गया।

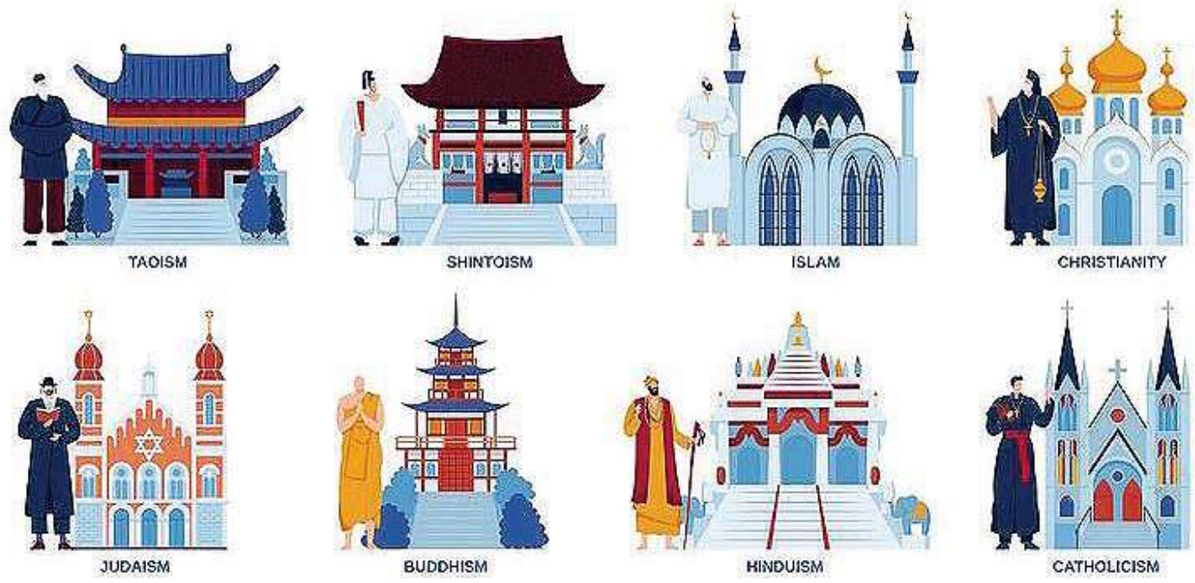

तत्कालीन सरकार और सरकार की नीतियों की हिमायत करने वालों ने इस कानून को भारत के साम्प्रदायिक ढांचे को बचाए रखने का प्रयास बताया और तारीफ की।

उपासना स्थल अधिनियम की धारा 4 (1) के अनुसार 15 अगस्त 1947 को विद्यमान किसी उपासना स्थल का धार्मिक स्वरुप वैसा ही बना रहेगा, जैसा कि वो 15 अगस्त 1947 को था। वहीं, धारा 4(2) में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरुप के परिवर्तन के संबंध में किसी भी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी और कोई नया मुकदमा या कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। यदि 15 अगस्त 1947 के बाद तथा इस अधिनियम के लागू होने से पहले किसी उपासना स्थल का धार्मिक स्वरुप बदला गया है और उससे संबंधित कोई वाद या अपील किसी न्यायालय में लंबित है, तो उसका निर्णय धारा 4(2) के अनुसार होगा। धारा 5 के अनुसार इस अधिनियम की कोई धारा राम जन्मभूमि/बाबरी मस्जिद मामले से संबंधित किसी भी मुकदमे अपील या कार्यवाही पर लागू नहीं होगी। इसी तरह धारा 6 के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लघंन करने पर अधिकतम 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।

> इस कानून को लेकर मई 2022 से देश भर में बहस-मुबाहिसों का दौर जारी है। दरअसल, 20 मई 2022 को ज्ञानवापी विवाद मामले की सुनवाई के दौरान देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मौखिक टिप्पणी की थी कि- उपासना स्थल अधिनियम में पूजा स्थल के वास्तविक स्वरूप का पता लगाने पर रोक नहीं है। इसके बाद 4 अगस्त 2023 को उच्चतम न्यायालय में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को स्थगित करने से इनकार कर दिया, जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) को मस्जिद परिसर में वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई थी।

यह अधिनियम ऐसे किसी पुरातात्त्विक स्थल पर लागू नहीं होता है, जो प्राचीन स्मारक और पुरातत्त्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 द्वारा संरक्षित है। यदि कोई वाद इस अधिनयम के लागू होने से पहले ही अंतिम रूप से निपटाया जा चुका है, तो ये अधिनियम उस वाद पर भी लागू नहीं होता है। इतना ही नहीं, यदि कोई विवाद जिसे इस अधिनियम के लागू होने से पहले ही दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति से सुलझाया जा चुका हो, तो उस पर भी यह अधिनियम लागू नहीं होता है।

इन्हीं सब प्रावधानों के चलते यह कानून हमेशा से विवादों का सबब रहा है। कानूनविदों में इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है कि यह न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, जो कि संविधान की एक बुनियादी विशेषता है।

इस कानून पर ताजा बहस देश भर की अदालतों में दायर हुई अर्जियों के चलते शुरू हुई है। दरअसल, राम मंदिर निर्माण के बाद हिन्दू धर्मस्थलों को लेकर सक्रिय हुए व्यक्तियों और संगठनों ने देश के कई राज्यों की अदालतों में कई धर्मस्थलों के स्थान पर हिन्दू धर्मस्थल होने को लेकर जांच करने के लिए अर्जियां दाखिल की हैं। ऐसे में पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने भी देश भर की सिविल अदालतों को अगले आदेश तक किसी भी पूजा स्थल के स्वामित्व और शीर्षक को चुनौती देने या विवादित धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षण का आदेश देने से रोक दिया था और यह स्पष्ट कर दिया कि कोई भी प्रभावी आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

उत्तरप्रदेश के संभल जिले में एक मस्जिद के स्थान पर हिंदू मंदिर के होने के दावे ने भी इस कानून पर बहस को हवा दी है।

जानकारों की मानें तो अभी उच्चतम न्यायालय में इस विषय से प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से जुड़ी कुछ याचिकाएं विचाराधीन हैं। इसके अलावा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दल इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग के साथ देश की सबसे बड़ी अदालत में जाने की तैयारी में हैं। उपासना स्थल अधिनियम का पक्ष लेने वालों का मानना है कि यह अधिनियम किसी विशेष धार्मिक समूह के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता, बल्कि देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस बीच, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी इस कानून को प्रभावी रूप से लागू करने की गुहार लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं, जहां फरवरी के दूसरे सप्ताह में सभी याचिकाओं पर सुनवाई होने की उम्मीद है। ऐसे में सभी पक्षों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।

पर्यटन बना 'विकसित भारत' के निर्माण का अभिन्न अंग

अचल सिंह मेड़तिया
वरिष्ठ पत्रकार

3500 पर्यटन सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करने के साथ हुई **पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी कार्यक्रम की शुरुआत**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 'विकास भी विरासत भी' के विजन के तहत विगत दस वर्षों में पर्यटन क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार हुए हैं, जिससे भारतीयों को न केवल सामाजिक-आर्थिक, बल्कि बौद्धिक रूप से भी लाभ हुआ है। देश ने 2014 के बाद से अपनी नीतियों और आकांक्षाओं में काफी परिवर्तन देखा है, जो विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के एक नए युग की शुरुआत है। पर्यटन को 'विकसित भारत' के निर्माण का अभिन्न अंग बनाने के लिए तीव्र प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यटन क्षेत्र में कुल 76.17 मिलियन नौकरियां सृजित की गई हैं। 'पर्यटन मित्र' और 'पर्यटन दीदी' कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। विदेशी मुद्रा आय 28.07 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है, जो 2014 की तुलना में 42.53 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

घरेलू पर्यटकों की संख्या में 95.64 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग 65 से सुधरकर 39 हो गई है। गंतव्य विकास परियोजनाओं पर 6,800 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं। विभिन्न राज्यों में कम ज्ञात पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 3,295.76 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ई-पर्यटक वीजा सुविधा आगंतुकों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई है।

समग्र सरकारी दृष्टिकोण के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय ने सफलतापूर्वक एक ऐसा इंको-सिस्टम बनाया है, जो न केवल दोनों क्षेत्रों के हितधारकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करता है, बल्कि महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को भी बढ़ावा देता है। यह दृष्टिकोण स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने में भी कारगर साबित हुआ है। पर्यटन क्षेत्र 2047 तक विकसित भारत में योगदान देने की राह पर है। लगभग 1,50,000 किलोमीटर सड़क नेटवर्क बिछाया गया है, 500 से अधिक नए हवाई मार्ग और 150 से अधिक नए हवाई अड्डे से हवाई संपर्क में वृद्धि हुई है, हाईस्पीड वंदे भारत ट्रेनें शुरू की गई है। लगभग 100 पर्यटन इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को पूरा किया गया है। भारत की जी-20 अध्यक्षता ने वैश्विक स्तर पर 60 से अधिक गंतव्यों को दृश्यता प्रदान की है। स्वच्छ भारत के कारण स्वच्छ गंतव्य, यूपीआई के माध्यम से बेहतर सुविधा और डिजिटल कनेक्टिविटी - 'समपूर्ण सरकार का दृष्टिकोण' के कारण पर्यटन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है।

पिछले दशक में सरकार ने स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी प्रमुख योजनाओं के माध्यम से 6,800 करोड़ रुपये से अधिक की कुल लागत से लगभग 120 परियोजनाओं को पूरा करके समग्र गतव्य विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। देश में कम ज्ञात पर्यटन स्थलों को सामने लाने के लिए, राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता के अंतर्गत 3,295.76 करोड़ रुपये की कुल लागत से पर्यटन इन्फ्रास्ट्रक्चर और पर्यटक अनुभव को बढ़ाने के लिए 23 राज्यों में 40 उच्च प्रभाव परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। परियोजनाओं के रूप में पूंजी निवेश को बढ़ावा देकर यह योजना स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास और स्थायी पर्यटन परियोजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसरों के सृजन की परिकल्पना करती है।

पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी कार्यक्रम की शुरुआत 6 गंतव्यों में कार्यक्रम के पायलट के हिस्से के रूप में लगभग 3,500 पर्यटन सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करने के साथ की गई थी, साथ ही 45 अन्य गंतव्यों में पहल को लागू किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यटकों को गंतव्यों में सकारात्मक और स्वागत करने वाला अनुभव मिले। गंतव्य में जमीनी स्तर पर बेहतर प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम को मजबूत और संवर्धित किया जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के लिए उद्योग का दर्जा प्रदान करने और उसे तागू करने में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रत्येक चरण में मार्गदर्शन प्रदान करने वाली एक पुस्तिका जारी की है, जिसका उद्देश्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में इस क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है।

भारत से फ्रांस की अटूट मित्रता का यह एक अद्वितीय प्रमाण होगा

केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और फ्रांस म्यूज़ियम डेवलपमेंट ने नई दिल्ली में बन रहे विश्व के सबसे बड़े युग युगीन राष्ट्रीय संग्रहालय को लेकर गत दिनों एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यह महत्वाकांक्षी परियोजना केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना का अभिन्न हिस्सा है और नार्थ व साउथ ब्लॉक में लगभग 1,55,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली है। युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय के एमओयू पर हस्ताक्षर के ये क्षण अत्यंत विशेष रहे, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस संकल्पना के साकार होने का ऐतिहासिक अवसर होगा। भारत की संस्कृति व विरासत की महानता और चिरकालीन भव्यता दुनिया के इस सबसे विशाल म्यूजियम में नजर आएगी। भारत से फ्रांस की अटूट मित्रता का भी यह एक अद्वितीय प्रमाण होगा। युग युगीन संग्रहालय भारत की गहरी सांस्कृतिक धरोहर को फ्रांस के संग्रहालय प्रबंधन और डिजाइन में विशेषज्ञता के साथ संयोजित करके एक वैश्विक सांस्कृतिक स्थल के रूप में कार्य करेगा। इस सहयोग के माध्यम से भारत और फ्रांस अपनी सांस्कृतिक साझेदारी को मजबूत करते हुए, धरोहर संरक्षण में अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों के लिए एक मापदंड स्थापित करेंगे।

भारत के प्रति दुनिया का आकांक्षा और कौतूहल का भाव बढ़ा है

भारत ने आर्थिक दृष्टिकोण से जिस गति के साथ में प्रगति की है, पूरा विश्व चमत्कृत दृष्टि से हमारी ओर देख रहा है। भारत को जानने, नए सिरे से पहचानने, भारत के प्रति आकांक्षा और कौतूहल का भाव पूरे विश्व भर में बढ़ा है। जो आने वाले समय में पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या को परिलक्षित करेगा। भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और सरकार के विभिन्न प्रयासों के चलते लोग गरीबी रेखा से बाहर निकाल कर मध्यम वर्ग की श्रृंखला में आए हैं। ऐसे लोग जब अपने घर से बाहर निकालकर देश को जानने के लिए धार्मिक स्थलों और अन्य पर्यटन स्थलों पर जिस दृष्टिकोण से जा रहे हैं, जिस गति के साथ जा रहे हैं, उससे बड़ी उछाल पर्यटकों की संख्या में दिखाई दी है।

नए पर्यटक स्थल विकसित कर रहे हैं

आने वाले समय में पर्यटकों की संख्या की गति और बढ़ेगी। इसी के चलते हुए भारत सरकार ने मौजूदा पर्यटन स्थलों के साथ वैकल्पिक पर्यटन विकास पर जोर दिया है। पर्यटकों का दबाव कम करने के लिए हम और नए पर्यटक स्थल विकसित कर रहे हैं। अभी हाल में हमने 3300 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की हैं। हम राज्यों के साथ मिलकर इस दिशा में और पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। पर्यटकों के दबाव के चलते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरह से दबाव बनता है, उसको लेकर भी प्रयास जारी हैं।

-गजेन्द्र सिंह शेखावत, केन्द्रीय संस्कृति एवम् पर्यटन मंत्री, भारत सरकार

ग्रहों की चाल

राजनीति और प्रशासनिक सेवा से जुड़े लोगों के लिए 15 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक समय कामकाज की दृष्टि से कैसा रहेगा, ज्योतिष की नजर में

मेष राशि

मेष राशि के राजनीतिज्ञों को भावनाओं और क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। कोई भी निर्णय बहुत संयमित होकर लें अन्यथा आगे चलकर पछताना पड़ सकता है। छोटी सी भी गलती आपके पद पर आंच ला सकती है। अपने किसी निकटस्त के कारण मान सम्मान खतरे में पड़ सकता है।

प्रशासनिक पद पर आसीन व्यक्तियों को ट्रांसफर या स्थान परिवर्तन जैसे समाचारों का सामना करना पड़ सकता है।

वृषभ राशि

मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। आय या धन से संबंधित कोई भी निर्णय बहुत सतर्कता के साथ लें। विवादों से बचकर चलें। भाग्य बिल्कुल साथ देता नहीं दिखाई दे रहा है। कार्यस्थल पर विभिन्न प्रकार के संघर्षों के साथ-साथ संतान को लेकर भी चिंता बनती हुई दिखाई दे रही है। भावावेश में निर्णय लेने से बचें। किसी बहुत नजदीकी राजनीतिक मित्र के साथ संबंधों में खिंचाव आ सकता है। अगर कोई भाई या बहन राजनीति में है तो उनके साथ भी विवाद की स्थिति बन सकती है।

प्रशासनिक पद पर आसीन अधिकारियों को बड़े निर्णयों को टाल देना बेहतर रहेगा।

मिथुन राशि

अपनी वाकपटुता और बुद्धि बल से समस्याओं का हल निकालने में सक्षम रहेंगे। किसी महत्वपूर्ण योजना के लिए फंड की प्राप्ति और साथ ही साथ उसका रिलीज भी होगा। लंबी यात्राओं से बचें अन्यथा चोट एक्सीडेंट इत्यादि का भय बना हुआ है। महिलाओं के साथ व्यवहार करते हुए सतर्कता बरतें। किसी महिला के कारण विवाद में पड़ सकते हैं। क्रोध या बहुत जोश में आकर निर्णय न लें। कार्यक्षेत्र में किसी पर भी आवश्यकता से अधिक भरोसा ना करें।

प्रशासनिक पद पर आसीन व्यक्तियों को इस समय बहुत सतर्कता की आवश्यकता रहेगी। मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। राजतांत्रिक सहयोग में कमी रहेगी।

कर्क राशि

आप अगले एक महा भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं साथ ही साथ चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। वाणी पर नियंत्रण आवश्यक रहेगा। आप सत्यवादी हैं किंतु लोग इस समय सत्य सुनने को तैयार नहीं है। अतः अपनी वाणी के कारण दूसरों से संबंध खराब हो सकते हैं। भाग्य बिल्कुल भी साथ देता हुआ नहीं दिख रहा है इसलिए अपने कर्म पर भरोसा रखें और संयम के साथ कदम आगे बढ़ाएं। 28 जनवरी के बाद का समय आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। यहां से आपका भाग्य साथ देता भी दिख रहा है।

प्रशासनिक पद पर आसीन अधिकारी दांपत्य जीवन से कुछ निराश दिख रहे हैं किंतु कार्य स्थल पर अपना दबदबा बनाए रखने में सफल प्रतीत होते हैं।

सिंह राशि

इस माह आकस्मिक यात्राओं का दौर दिखाई दे रहा है। भाग दौड़ रहेगी। साथ ही साथ आपको अपने आला कमान और अन्य वरिष्ठ जनों के साथ सामंजस्य बिठाने में तकलीफ होती दिख रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय उत्तम है किंतु आपके कोई गुप्त शत्रु आप पर लांछन लगाने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। पत्नी के साथ संबंधों में थोड़ी सी तल्खी आ सकती है।

प्रशासनिक पद पर उपस्थित व्यक्तियों को अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा में ऊर्जा व्यय होती प्रतीत हो रही है। किसी भी विवाद की स्थिति में ना उलझें। विभागीय राजनीति का शिकार हो सकते हैं।

कन्या राशि

आप अगर अपने बुद्धि बल पर निर्णय लेते हैं तो काफी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों की बातों में बहुत जल्दी ना आए। थोड़ी भाग दौड़ रहेगी लेकिन अंतत आप आने वाली हर चुनौती का हल निकालने में सफल होंगे। आपकी चौतरफा तारीफ की जाएगी और आपके कार्यों को सारा जाएगा। यह समय आपके लिए कर्म प्रधान है। अतः भाग्य का मुंह ना देखें। कर्म करते चले जाएं तो आपको निश्चित रूप से शुभ फल की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और आप अपने वरिष्ठ जनों के प्रिय होंगे।

प्रशासनिक पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के लिए समय लाभकारी है। आपको पदोन्नति मिल सकती है या फिर अतिरिक्त पदभार दिया जा सकता है। जिसे आप बखूबी निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेष रूप से फाइनेंस से संबंधित अधिकारी इस बीच बड़े निर्णय लेंगे और सम्मान भी प्राप्त करेंगे।

ग्रहों की चाल

तुला राशि

यह समय आपके लिए कष्टकारी है। आपके द्वारा दिए गए प्रपोजल रद्द हो सकते हैं। साथ ही मान सम्मान को भी ठेस पहुंचती दिखाई दे रही है। हालांकि शत्रुहंता योग बन रहा है, जिसका अर्थ है कि शत्रु सिर नहीं उठा पाएंगे। आप अपने आसपास की परवाह किए बगैर ईमानदारी से काम करते रहें तो माह के अंत में आपको नोटिस किया जाएगा और आपके काम की तारीफ की जाएगी। प्रशासनिक पद पर आसीन व्यक्तियों के लिए यह समय उत्तम है। मंत्रालयों में अपनी बात मनवाने में आप सक्षम रहेंगे। आपके द्वारा जनहित में रखे गए प्रपोजल स्वीकार किए जाएंगे। आपका मन प्रसन्न रहेगा। अपने अधिकारों का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर पाएंगे।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के राजनीतिज्ञों का यह समय अति उत्तम कहा जाएगा। आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि प्राप्त होगी। आकस्मिक धन लाभ का भी योग बन रहा है। कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट फलीभूत होते दिखाई दे रही है। आप किसी न्यायिक कमेटी या अन्य किसी बोर्ड का प्रतिनिधित्व करेंगे। आपको न्याय करने के अवसर प्राप्त होंगे जिसमें आप सफल रहेंगे। विदेश योग भी आपके लिए बन रहा है। सहयोगियों के साथ किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में ना पड़ें।

वृश्चिक राशि के अधिकारी आवश्यकता से अधिक रिस्क ना लें। अपने बुद्धि और वाणी का उपयोग करके आप किसी भी समस्या का हल निकालने में सक्षम रहेंगे। धैर्य पूर्वक लिए गए निर्णय सफल होंगे। विदेश की प्लानिंग या जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है।

धनु राशि

आपका यह माह उत्तम स्वास्थ्य के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ आवश्यक मीटिंग्स रहेंगी जिनका फल पूर्ण रूप से सफलता के साथ प्राप्त होगा। आपकी बुद्धि की तारीफ की जाएगी। आपके निर्णयों का स्वागत किया जाएगा। कीमती वस्तुओं का ध्यान रखें और साथ ही इस बीच आपका संचित धन नष्ट हो सकता है। कुछ भ्रम की स्थिति बनी हुई दिखाई दे रही है और गुप्त शत्रुओं से आपको खतरा दिखाई दे रहा है। जल से कोई दुर्घटना हो सकती है। बाथरूम इत्यादि में फिसलन का भी ध्यान रखें। सहयोगी आपके साथ धोखा कर सकते हैं अतः सतर्कता बरतें।

धनु राशि के प्रशासनिक वर्ग को अंदरूनी राजनीति का शिकार होना पड़ सकता है। अपने आंख, नाक, कान खुले रखें और चौकन्ना रहे। चोट और एक्सीडेंट के प्रति भी सतर्कता रखनी आवश्यक रहेगी। बड़े निर्णय आवेग में ना लें। कई बार सोच समझकर ही निर्णय लें।

मकर राशि

मकर राशि के लिए समय अत्यधिक शुभ है। आप भरपूर तरीके से शासन करेंगे। आपके निर्णयों में परिपक्वता दिखाई दे रही है, जिनका स्वागत होगा। अपने आप पर भरोसा रखें। दूसरों के कहे में बहुत जल्दी ना आएं। अध्यात्म की ओर आपका झुकाव होगा और कुछ मंदिरों के दर्शन भी करेंगे। किसी

धार्मिक संस्थान के शिलान्यास या उद्घाटन का कार्य भी आपके हाथों से संपन्न होता दिखाई दे रहा है।

प्रशासनिक पद पर आसीन व्यक्तियों के लिए यह समय अत्यधिक लाभकारी है। कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों में आपकी विशेष भागीदारी दिखाई पड़ रही है। आप उचित मान सम्मान प्राप्त करते दिख रहे हैं। आपकी कही हुई कुछ पुरानी बातें इस बीच सत्य होती दिख रही हैं।

कुंभ राशि

राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े और पदासीन व्यक्तियों के लिए यह समय अच्छा नहीं है। आप भ्रम की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। निर्णय लेने की क्षमता कमजोर रहेगी। आत्मविश्वास में कमी दिखाई पड़ रही है। कोई बहुत कीमती वस्तु के को जाने का भाई है। आपका पद को लेकर स्थिरता देने में आपकी कुछ ऊर्जा जाती दिखाई दे रही है। गुप्त शत्रु आपकी स्थिति का लाभ उठा सकते हैं। विशेष कर महिलाओं से सतर्क रहें अन्यथा मान सम्मान को चोट पहुंच सकती है। आकस्मिक व्यय का समय है। इस बीच कुछ परियोजनाओं के लिए धन के आवंटन का कोई दृश्य बन सकता है। आर्थिक रूप से आप संबल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

प्रशासनिक पद पर आसीन कुंभ राशि के व्यक्तियों के लिए समय अति उत्तम है। किंतु इस बीच किए गए किसी हस्ताक्षर की वजह से भविष्य में आपको संकट आ सकता है। अत हर दस्तावेज सूझबूझ और विवेक के साथ हस्ताक्षर करें। नेत्र दोष के प्रति सतर्क रहें। किसी के बहकावे में ना आएं।

मीन राशि

जो निर्णय बहुत महत्वपूर्ण ना हों उनको इस बीच टाल दें। धूर्त व्यक्तियों को अपने दायरे से बाहर रखें। चाटुकारों से अपना बचाव करें। यह लोग किसी षड्यंत्र के तहत आपके करीब आकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आय के साधनों में कमी होती दिखाई दे रही है। किंतु राजनीति के अतिरिक्त अगर कोई व्यवसाय है तो वहां पर वृद्धि होती दिख रही है। निजी तौर पर किसी भूखंड के खरीदारी के भी योग बन रहे हैं। यह समय मिले-जुले असर वाला है और जरूरी है कि आप सतर्कता पूर्वक इस समय को पर करें।

मीन राशि के पदाधिकारी इस बीच काफी सुकून महसूस करेंगे। आपके ऊपर कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां आती दिखाई दे रही है जिन्हें आप बखूबी निभा लेंगे। आपको कोई अवार्ड या अन्य प्रकार का मान सम्मान प्राप्त हो सकता है।

लेखक : विपुल दोभाल

ईमेल : vipravaani@gmail.com | **मोबाइल : 9928424374**

वो सेल्समैन जो बन गए हिंदी सिनेमा के पहले सुपर स्टार

के एल सहगल

सुधांशु टाक
लेखक, समीक्षक

हिंदी सिनेमा में अब तक एक से बढ़कर नायाब कलाकार आए और छा गए। अब तक के सफर की बात करें तो अशोक कुमार, राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सुपरस्टार ने हिंदी सिनेमा के परदे को रोशन किया। इन सभी का अपने जमाने मे बड़ा और जबरदस्त क्रेज रहा है। लेकिन इन सबसे भी पहले ये रुतबा एक ऐसे स्टार को हासिल था, जिसका दीवाना उस दौर का प्रत्येक सिने प्रेमी था। बाद के ये सुपर स्टार जैसे दिलीप कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन तक भी इसी स्टार के दीवाने थे और इसे कॉपी करते थे। इस अभिनेता का नाम था कुंदन लाल सहगल यानी के एल सहगल।

ये सहगल साहब हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार कहे जाते हैं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि उन्होंने रेलवे टाइमकीपर जैसा काम कर पैसा कमाना शुरू किया और बाद में में वे टाइपराइटर सेल्समैन का काम भी करने लगे थे। लेकिन जब वे फिल्मों में आए तो अपने जमाने के रॉकस्टार बन गए। उस जमाने में लोग उनकी सिंगिंग को लेकर क्रेजी थे और एक्टिंग के दीवाने।

जम्मू रियासत के तहसीलदार अमरचंद सहगल के घर 11 अप्रैल 1904 को उनका जन्म हुआ था। जालंधर से वास्ता रखने वाले अमरचंद के दो बेटे थे – रामलाल और हजारीलाल। तीसरे का नाम रखा गया कुंदन लाल।

कुंदन बचपन से ही अपनी मां को रोज सुबह भजन गाते देखते थे। रात को उनसे लोरी सुनते तभी नींद लेते। स्कूल जाने लगे तो पढ़ाई में मन नहीं लगता लेकिन गाना सुनाने को कहो तो रेडी रहते थे। जंगल में चिड़िया का चहचहाना सुनते, गडरियों के लोकगीत सुनते, घर में मनोयोग से भजन गाते। यहीं से संगीत उनमें स्थाई रूप से बस गया। बड़े होने लगे तो मां के गाए भजनों को हूबहू वैसे ही गाकर सुनाने लगे। जीवन के आखिरी दिनों तक कुंदन धार्मिक रहे। उनके तीन बच्चे हो गए थे। वे सुनते रहते थे और कुंदन रोज भजन गाते थे। लेकिन उन्हें शराब की बुरी लत लग चुकी थी ।वे रोज सुबह उठकर हार्मोनियम लेकर बालकनी में बैठ जाते थे और दो भजन गाते थे– "उठो सोनेवालों सहर हो गई है, उठो रात सारी बसर हो गई है" और "पी ले रे तू ओ मतवाला, हरी नाम का प्याला।"

फिर वे कलकत्ता चले गए वहां घूम-घूमकर साड़ियां बेचने का काम किया। इसके बाद वे न्यू थियेटर्स स्टूडियो से जुड़े जहां से उनकी फिल्मी यात्रा शुरू हुई। यहां तक पहुंचने में सहगल को 13-14 साल लगे। कुछ वक्त बाद 16 जनवरी 1932 को फिल्मों में उनकी एंट्री हुई। वो फिल्म थी 'मोहब्बत के आंसू' से। वे हीरो भी थे और इसके गाने भी गाए थे। फिल्म नहीं चली। अगले साल उनकी चार फिल्में आईं जिनमें दो में उन्होंने भजन गाए थे। दो में एक्टिंग की। 'पूरण भगत' में उनके भजन बड़े लोकप्रिय हुए। लेकिन ये तीसरे साल आई फिल्म 'चंडीदास' थी जिसके बाद उन्हें पलटकर नहीं देखना पड़ा।

और ये 1935 का साल था जब एक सुपरस्टार के तौर पर उनका जन्म हुआ। फिल्म थी शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के फेमस नॉवेल पर बनी 'देवदास'।

उनकी फिल्मों के गानों ने भी पूरे भारत में लोगों को दीवाना किया हुआ था। जैसे 1937 में आई फिल्म 'प्रेसिडेंट' का 'गाना इक बंगला बने न्यारा'।

इसके 32 साल बाद आई ब्लॉकबस्टर 'दो रास्ते' (1969) में बलराज साहनी का किरदार सहगल के इसी गाने को सुनता रहता है। कहानी भी घर बचाने के संघर्ष पर आधारित होती है। ये गाना उसका रेफरेंस पॉइंट था। इसी फिल्म में राजेश खन्ना भी थे जिन्होंने साहनी के सबसे छोटे भाई का रोल किया था। इस फिल्म में साहनी का पात्र जैसे फैन की तरह सहगल का ये गाना सुनता था, वो दीवानगी भारत भर के लोगों में रही।

बचपन में उन्होंने संगीत की विधिवत शिक्षा नहीं ली लेकिन संघर्ष के दिनों में जरूर अलग-अलग जगह से सीखने की कोशिश करते रहे। कानपुर में वे पेट पालने के लिए दिन में रैमिंग्टन के टाइपराइटर बेचा करते थे। लेकिन शाम को उस्तादों के साथ संगत करते थे। भैरवी जैसे राग सीखते थे. इसी शहर में उनकी एक गुरु-मां बन गई थीं जिनसे वो ठुमरी और दादरा सीखते थे।

1947 की शूटिंग : जब दिलीप कुमार ने कहा था...

सहगल साहब के पास पहुंचना एक मंजिल तय करने के बराबर था

सहगल का स्टारडम कैसा था इसे दिलीप कुमार के शब्दों में मुकम्मल रूप में जान सकते हैं. बॉम्बे टॉकीज़ में दिलीप कुमार अपनी फिल्म 'मिलन' (1947) की शूटिंग कर रहे थे. इसके डायरेक्टर नितिन बोस थे. पास ही में किसी और फिल्म का मुहुर्त चल रहा था. बोस और दिलीप भी वहीं थे. दिलीप साब ने इस अनुभव को यूं याद किया,

> "मुझे अच्छी तरह याद है नितिन बाबू ने कहा था आओ हम तुम्हे किसी ख़ास दोस्त से मिलाते हैं. उस दिन मुहुर्त के मेहमानों में चंद्रमोहन साहब भी थे, अशोक भैय्या भी थे, और वहीं कहीं मोती भैय्या की हंसी भी गूंज रही थी. और सामने, दूर.. मेरे सामने ही सहगल साहब एक कुर्सी पर, सफेद कुर्ता और सफेद पायजामा पहनकर बैठे थे. **अब इन तमाम बड़े-बड़े आर्टिस्टों के सामने से होकर सहगल साहब तक पहुंचना भी मेरे लिए एक मंजिल तय करने के बराबर था.**

..जब नितिन बाबू ने मेरा तार्रुफ करवाया उनसे तो वो बड़ी ही शफक़त से मिले. मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया. मुख्तसर बातें कीं. उनकी उन बातों में बहुत ही अपनापन और सादगी थी. मुझे ऐसे लगा जैसे, अपने ही घर का कोई बुजुर्ग मुझसे बातें कर रहा हो. थोड़ी देर बाद वो किसी ख़याल में खो गए. और दूर आम के पेड़ों पर टकटकी लगाए यूं देख रहे थे जैसे मन ही मन में कुछ गुनगुना रहे हों."

नई पीढ़ी ने भले ही सहगल के गानों को मज़ाक का पात्र समझा हो लेकिन दिलीप साहब ने उसे यूं देखा था, "उनकी एक फिल्म थी जिसका नाम था 'ज़िंदगी'. उस फिल्म का वो आखिरी दर्दनाक सीन मुझे कभी नहीं भूलता. जिसमें निहायत ही मतीन अंदाज में सहगल साब फिल्म की हीरोइन जमना की लाश के पास बैठे हुए थे और अपनी महबूबा की मौत का सारा कर्ब, सारी रूहानी तकलीफ उनके उस गाने में ढल गई, जो उन्होंने उस वक्त गाया थाः सो जा, सो जा, सो जा राजकुमारी सो जा."

- सहगल ने हिंदी, बंगाली और तमिल भाषा की 36 फिल्मों में अभिनय किया था. ज्यादातर हिंदी थीं. उन्होंने 185 के करीब गाने गाए. इनमें 110 हिंदी और बाकी ज्यादातर बंगाली थे. जब 1937 में उनकी पहली बंगाली फिल्म 'दीदी' रिलीज हुई तो सामान्य और संभ्रांत दोनों वर्ग के दर्शक उनके मुरीद हो गए.
- सहगल की आवाज की लोकप्रियता का यह आलम था कि कभी भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा रेडियो सीलोन कई साल तक हर सुबह सात बज कर 57 मिनट पर इस गायक का गीत बजाता था .
- सहगल की आवाज लोगों की दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन गई थी. वे रवीन्द्र संगीत गाने का सम्मान पाने वाले पहले गैर बांग्ला गायक थे. यह वह समय था जब भारतीय फिल्म उद्योग मुंबई में नहीं बल्कि कलकत्ता में केंद्रित था. उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस जमाने में उनकी शैली में गाना अपने आपमें सफलता की कुंजी मानी जाती थी.
- एक समय में जब पंजाबी होने के कारण उनसे बंगाली गाने गवाने और एक्टिंग करवाने को लेकर साफ मना कर दिया, उन्हीं के बंगाली गायन को इस फिल्म में इतना पसंद किया गया कि खुद रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा था, "तुम्हारा गला कितना सुंदर है."
- कलकत्ता और बंबई की फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने 15 साल काम किया. 1947 में उनकी आखिरी फिल्म 'परवाना' रिलीज हुई, उनकी मृत्यु के बाद. शराब ने उन्हें जिलाए भी रखा, और जीने भी नहीं दिया.

> सहगल के स्टारडम का पहला दशक चल रहा था और एक बच्ची थी जो उनकी दीवानी थी. नाम था लता. लता मंगेशकर. आज जिन लता मंगेशकर की सिंगिंग मौलिकता और विशुद्धता का बहुत ऊंचा पैमाना है, वे लता म्यूजिक सीखने के शुरुआती वर्षों में सहगल की तरह गाने की कोशिश करती थीं. घर में फिल्मी गानों को गाना पसंद नहीं किया जाता था लेकिन लता को छूट थी. वे अपने पिता के साथ सहगल के गाने गाती रहतीं. सहगल की वे ऐसी दीवानी थीं कि उनसे शादी करने के सपने देखती थीं. लता ने एक बार बताया, "जितना मुझे याद आता है, मैं हमेशा से के. एल. सहगल से मिलना चाहती थी. बच्चे के तौर पर मैं कहती थी – जब बड़ी हो जाऊंगी तो उनसे शादी करूंगी. तब मेरे बाबा मुझे समझाते थे कि जब तुम शादी करने जितनी बड़ी हो जाओगी तो सहगल साब शादी की उम्र पार कर चुके होंगे." लता को ये अफसोस हमेशा रहा कि वे जीवन में कभी सहगल से नहीं मिल पाईं. वे एक तरह से उनके परोक्ष म्यूजिक गुरु भी थे. जैसे कि हिंदी सिनेमा के लैजेंडरी सिंगर-एक्टर किशोर कुमार भी सहगल के बड़े प्रशंसक थे. वे भी सहगल को अपना म्यूजिकल गुरु मानते थे. वे पहले-पहल बंबई आए ही इसलिए थे कि बस एक बार सहगल से मिल सकें.
> पाकिस्तानी शायर अफ़ज़ाल अहमद सैयद के शब्दों में - 'सिनेमा का संगीत सहगल ने ईजाद किया। फ़क़ीरों-सा बैराग, साधुओं-सी उदारता, मौनियों-सी आवाज़, हज़ार भाषाओं का इल्म रखने वाली आंखें, रात के पिछले पहर गूंजने वाली सिसकी जैसी ख़ामोशी, और पुराने वक़्तों के रिकार्ड की तरह पूरे माहौल में हाहाकार मचाती एक सरसराहट। वह कौन-सी गंगोत्री है, जहां से निकल कर आती है सहगल की आवाज़ ?'

सहगल जनवरी, 1947 में केवल 43 वर्ष की उम्र में इस संसार को अलविदा कह गए थे. 18 जनवरी को उनकी पुण्यतिथि है। 'राजस्थान टुडे' की ओर से उनकी पुनीत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि। शत शत नमन

राजनीति के क्षितिज पर पश्चिम से उदय हुआ रवि

राजस्थान टुडे ब्यूरो

यूं तो रवि पूर्व से उदय होता है, लेकिन राजनीतिक क्षितिज पर रवि का उदय किसी भी दिशा में हो सकता है। करीब 15 महीने पहले राजनीतिक क्षेत्र में एक ऐसे युवा सितारे का पश्चिम से उदय हुआ, जिसकी चर्चा लगातार जारी है। चर्चा का आलम यह है कि ना तो सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर यूजर्स और रील बनाने वालों को फुर्सत है, ना ही राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ियों व प्रशासनिक अधिकारियों को ठीक से सांस लेने दी जा रही है। इस युवा राजनीतिक सितारे का नाम रविंद्र सिंह भाटी है, जिसे उनके चाहने वाले प्यार से रवसा कहते हैं।

देश के पश्चिमी हिस्से में पाकिस्तान से सटी बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा क्षेत्र के 27 वर्षीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करीब 28 लाख फॉलोअर्स है। दूसरे नंबर पर जो राजनीतिज्ञ है, उनके फॉलोअर्स रविंद्र सिंह भाटी के आधे भी नहीं है। इस आंकड़े से ही समझा जा सकता है कि इस युवा ने किस कदर गदर मचा रखा है। साहस का आलम यह है कि थोड़े दिन पहले एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि जैसलमेर जिले के बईया गांव में ओरण भूमि बचाने की आपने जो मुहिम चला रखी है, वह भूमि राज्य सरकार ने गौतम अडानी की फर्म को सौर ऊर्जा के लिए आवंटित कर रखी है। प्रश्न पूरा होने से पहले ही वह तपाक से जवाब देते हैं-अडानी धणी थोड़ी ही है अर्थात अदानी मालिक नहीं है। असली मालिक जनता है और जिस जमीन के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, वह हमारे पूर्वजों ने अपनी जान की बाजी लगाकर गोवंश के लिए आरक्षित की है। ऐसे में सरकार को झुकना पड़ेगा। करीब 62 दिन तक आंदोलन चलने के बाद 7 जनवरी को वास्तव में राज्य सरकार झुक गई और अडानी को आवंटित की गई गोचर भूमि को आवंटन के दायरे से बाहर कर दिया गया।

भाजपा के लिए गले की फांस

रविंद्र सिंह भाटी का क्रेज बच्चों से लेकर महिलाओं और बुजुर्गों तक हर वर्ग में है। बीते विधानसभा चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय चुनाव लड़कर भाजपा व कांग्रेस दोनों को चित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की तो जमानत जप्त हो गई। विधानसभा चुनाव के ठीक बाद हुए लोकसभा चुनाव में भाटी ने एक बार फिर निर्दलीय ताल ठोक दी। हालांकि इस बार वह चुनाव नहीं जीत पाए लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी बमुश्किल अपनी जमानत बचाकर तीसरे नंबर पर रहे। रविंद्र सिंह को करीब 6 लाख वोट मिले। इन दो चुनाव के बाद भाटी भारतीय जनता पार्टी की आंख की किरकिरी और गले की फांस बने हुए हैं। भाजपा उन्हें अंदरखाने चित्त करने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक कोई दांव काम नहीं कर रहा है। एक तरह से पार्टी खुद का नुकसान करती हुई नजर आ रही है। इसका नतीजा आने वाले पंचायत चुनाव में देखने को भी मिल सकता है।

अंदाज़-ए-बयां
आक्रामक

युवा विधायक भाटी की शैली काफी आक्रामक है, जिसके चलते बीते 1 वर्ष में कई सुर्खियां बनी है। ताजा घटनाक्रम के तहत आधी रात को रविंद्र सिंह भाटी एक सोलर कंपनी के काम को रुकवाने अपने विधानसभा क्षेत्र के हड़वा गांव पहुंच जाते हैं। वह काम रुकवा देते हैं, जिस पर गांव के पूर्व सरपंच के साथ उनकी गरमा गरम बहस होती है। अगले दिन इस बहस का वीडियो सुर्खियां बन जाता है। इसी तरह एक महीने पहले बईया गांव में वह पुलिस जीप से दो युवाओं को नीचे उतरने का इशारा करते हैं, युवा उतर जाते है और पुलिस देखती रह जाती है। तीन दिन बाद जैसलमेर एसपी भाटी के खिलाफ राज कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करने का फैसला लेते हैं। इसी तरह कुछ महीने पहले बिजली कटौती को लेकर ग्रामीणों का पक्ष रखते हुए भाटी गडरारोड के सहायक अभियंता को फटकार लगाते हैं। भाटी के जाने के बाद ग्रामीण अभियंता से भिड़ जाते है। युवा विधायक का यह आक्रामक अंदाज सरकारी मीटिंगों में भी अकसर देखने को मिल जाता है।

जैसलमेर जिले के बईया गांव में ओरण बचाओ मुहिम के तहत रात्रि विश्राम के बाद अलसुबह ओरण क्षेत्र में रविंद्र सिंह भाटी।

अलग ही धुन पर सवार... ऊर्जा से लबरेज रविंद्र सिंह भाटी अलग ही धुन पर सवार है। सुबह से लेकर शाम तक उन्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा जिलों के अलावा राज्य व देश भर से आने वाले निमंत्रण उन्हें लगातार व्यस्त रखे हुए हैं। हालांकि वह अपना अधिकांश समय लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर व अपने विधानसभा क्षेत्र शिव को ही दे रहे है, लेकिन फिलहाल उनके पास समय देने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। उनके विधायक कोटे के कार्य भी सरकार ने किसी ने किसी बहाने अटका रखे हैं। अधिकांश स्वीकृतियां कागजों में ही है, वह धरातल पर नहीं उतर पाई है। इन हालात में भाटी ने जनता से जुड़े रहने का एक अलग ही तरीका निकाल दिया है। बीते 1 वर्ष में उन्होंने अपने क्षेत्र में निजी क्षेत्र के सहयोग से विभिन्न विदेशी भाषाओं के कोर्सेज, चिकित्सकों के विशेष दल के जरिए चिकित्सा शिविर, बुजुर्गों के लिए हरिद्वार की तीर्थ यात्रा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म फेस्ट जैसे कई कार्यक्रम चला रखे हैं। कुल मिलाकर फिलहाल वह युवा सनसनी बने हुए हैं।

भारत के डिजिटल भविष्य का नया स्वरूप
डेटा सुरक्षा के लिए नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण

अश्विनी वैष्णव केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना और प्रसारण तथा रेलवे मंत्री

"जब हम वैश्विक भविष्य के बारे में बात करते हैं, तो मानव-केंद्रित दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए।" हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के 'भविष्य के शिखर सम्मेलन' में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ये शब्द, लोगों को पहले रखने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। इस दर्शन ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) नियम, 2025 के मसौदे को आकार देने में हमारे प्रयासों का मार्गदर्शन किया है। अंतिम रूप दिए जाने के बाद, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 को लागू हो जाएगा, जो नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा के अधिकार की रक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करेगा।

सशक्तिकरण का एक नया युग

भारतीय नागरिक डीपीडीपी नियम, 2025 के केंद्र में है। डेटा के बढ़ते वर्चस्व वाली दुनिया में, हमारा मानना है कि व्यक्तियों को शासन की रूपरेखा के केंद्र में रखना अनिवार्य है। ये नियम नागरिकों को कई अधिकारों से सशक्त बनाते हैं, जैसे सूचना आधारित सहमति, डेटा मिटाने की सुविधा और डिजिटल रूप में नामांकित व्यक्ति को नियुक्त करने की क्षमता, आदि। नागरिक अब उल्लंघनों या अनधिकृत डेटा उपयोग के सामने असहाय महसूस नहीं करेंगे। उनके पास अपनी डिजिटल पहचान को प्रभावी ढंग से सुरक्षित और प्रबंधित करने के लिए उपकरण होंगे।

नियमों को सरलता और स्पष्टता के साथ तैयार किया गया है, यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक भारतीय, चाहे उनके पास तकनीकी ज्ञान कुछ भी हो, अपने अधिकारों को समझ सकता है और उनका प्रयोग कर सकता है। सहमति स्पष्ट शब्दों में मांगी जाती है तथा नागरिकों को अंग्रेजी या संविधान में सूचीबद्ध 22 भारतीय भाषाओं में से किसी में भी जानकारी प्रदान करना अनिवार्य किया गया है, यह रूपरेखा समावेशिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

बच्चों की सुरक्षा

डिजिटल युग में बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता है। इसे मान्यता देते हुए, नियम नाबालिगों के व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के लिए माता-पिता या अभिभावक की सत्यापन योग्य सहमति को अनिवार्य बनाते हैं। अतिरिक्त सुरक्षा उपाय बच्चों को शोषण, अनधिकृत प्रोफाइल बनाने और अन्य डिजिटल नुकसान से बचाव सुनिश्चित करते हैं। ये प्रावधान भविष्य की पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित डिजिटल परिदृश्य बनाने के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाते हैं।

विनियमन के साथ विकास का संतुलन

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था एक वैश्विक सफलता की गाथा रही है और हम इस गति को बनाए रखने के प्रति दृढ़ हैं। हमारी रूपरेखा, डिजिटल अर्थव्यवस्था में नवाचार को सक्षम करते हुए नागरिकों के लिए व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करती है। विनियमन पर बहुत अधिक जोर देने वाले कुछ अंतरराष्ट्रीय प्रारूपों के विपरीत, हमारा दृष्टिकोण व्यावहारिक और विकासोन्मुखी है। यह संतुलन सुनिश्चित करता है कि नागरिकों की सुरक्षा की जाए और नवाचार भावना को दबाया न जाए, जो हमारे स्टार्टअप और व्यवसायों को प्रेरित करती है।

छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप के लिए अनुपालन बोझ कम हो जाएगा। हितधारकों की अलग-अलग क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, नियमों को वर्गीकृत जिम्मेदारियों के साथ डिज़ाइन किया गया है। डेटा विश्वास के मूल्यांकन के आधार पर, बड़ी कंपनियों के पास उच्च दायित्व होंगे, जो विकास को बाधित किए बिना जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे।

डिजिटल-प्रथम दर्शन

इन नियमों के मूल में "डिजाइन से डिजिटल" दर्शन है। डेटा सुरक्षा बोर्ड मुख्य रूप से एक डिजिटल कार्यालय के रूप में कार्य करेगा, जिसे शिकायतों का समाधान करने और अनुपालन लागू करने का काम सौंपा गया है। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, हम दक्षता, पारदर्शिता और गति सुनिश्चित करते हैं। नागरिक शारीरिक उपस्थिति के बिना भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, प्रगति की निगरानी कर सकते हैं और समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

यह डिजिटल-प्रथम दृष्टिकोण सहमति व्यवस्था और डेटा प्रबंधन कार्य तक फैला हुआ है। प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, हम बड़ी कंपनियों के लिए अनुपालन करना और नागरिकों के लिए जुड़ना आसान बनाते हैं, जिससे प्रणाली में विश्वास बढ़ता है।

समावेशी दृष्टिकोण

इन नियमों की यात्रा उनके अभिप्राय जितनी ही समावेशी रही है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के सिद्धांतों पर आधारित, मसौदा नियम विभिन्न हितधारकों से एकत्र किए गए व्यापक इनपुट और वैश्विक सर्वोत्तम तौर-तरीकों के अध्ययन का परिणाम है।

नागरिकों, व्यवसायों और नागरिक समाज से प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित करते हुए, हमने सार्वजनिक परामर्श के लिए 45-दिनों की अवधि निर्धारित की है। यह जुड़ाव सामूहिक ज्ञान और भागीदारीपूर्ण नीति निर्माण के महत्व में हमारे विश्वास का प्रमाण है, जबकि यह सुनिश्चित करना है कि यह व्यवस्था न केवल मजबूत हो, बल्कि हमारे सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य की अनूठी चुनौतियों के अनुकूल भी हो।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिक अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक हैं, नागरिकों को उनके व्यक्तिगत डेटा से जुड़े अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए व्यापक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

भविष्य के लिए एक विजन

इन नियमों की शुरुआत के साथ, हम न केवल वर्तमान चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं बल्कि एक सुरक्षित और अभिनव डिजिटल भविष्य की आधारशिला भी रख रहे हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 का मसौदा वैश्विक डेटा शासन मानदंडों को आकार देने में भारत के नेतृत्व को प्रतिबिंबित करता है। नागरिकों को केंद्र में रखते हुए, नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देकर, हम एक मिसाल कायम कर रहे हैं, जिसका दुनिया अनुसरण कर सकती है।

हमारी प्रतिबद्धता स्पष्ट है: इस डिजिटल युग में हर भारतीय को सुरक्षित, सशक्त व सक्षम बनाना। मैं प्रत्येक नागरिक, व्यवसाय व नागरिक समाज समूह को परामर्श अवधि के दौरान टिप्पणियाँ व सुझाव साझा करके इस संवाद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। आइए हम मिलकर इन नियमों को परिष्कृत करें ताकि एक ऐसी व्यवस्था तैयार हो सके, जो वास्तव में एक सुरक्षित, समावेशी और संपन्न डिजिटल भारत की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती हो।

राजस्थान पत्रिका जोधपुर संस्करण के 46 वें स्थापना पर हार्दिक शुभकामनाएँ।
नव शिक्षा समाज द्वारा संचालित
SIR PRATAP VIDHI MAHAVIDYALAYA
A LEADING LAW COLLEGE IN WESTERN RAJASTHAN
Affiliated to Dr. Bhimrao Ambedkar Law University, Jaipur
Approved by bar council of India
LL.B 3 Years Programme Eligibility- Graduation in Any Stream
B.A. LL.B 5 Years Programme Eligibility- 12th in Any Stream
WHY CHOOSE US?
Affordable free Structure.
Online Support Resources.
Centrally Located.
Rich Library with Law Journals, E-Journals and Research Facilities.
Dedicated and Experienced Faculties.
Attractive Scholarship Schemes for Meritorious and Needy Students.
Interaction with Judges, Lawyers and Academicians.
Active Legal Aid Cell.
Moot Court Debates and Workshops.
Interactive & Integrated Teaching Methodology with Regular Case Studies.
Internship with Experienced and Senior Advocates and Law Firms
MGH ROAD, JODHPUR- 342001 (Raj)
0291-2959866, 6378800229, 9414145735, 9460155558
Info.spmjodh@gmail.com Facebook.com/sirpratapjod
For Online Registration Logon to : www.spvm.co.in
सर प्रताप कॉलेज
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त
न्यूनतम फीस
योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा अध्यापन
ऑनलाईन शिक्षण व्यवस्था
अंग्रेजी माध्यम की छात्राओं हेतु अलग व्यवस्था
अत्याधुनिक पुस्तकालय
ई-लाईब्रेरी की सुविधा
सी.सी.टी.वी कैमरा युक्त कॉलेज परिसर
B.A.
नई शिक्षा नीति 2020 सेमेस्टर प्रणाली के अनुरूप
इतिहास, राजनीति विज्ञान समाज शास्त्र, भूगोल, हिन्दी साहित्य, अर्थशास्त्र लोक प्रशासन
MGH ROAD, JODHPUR- 342001 (Raj)
spcjodh@gmail.com 6378399366
गिरीश माथुर अध्यक्ष
डी डी माथुर सचिव
निर्मल माथुर कोषाध्यक्ष
एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्य, नव शिक्षा समाज
SIR PRATAP SR. SEC. SCHOOL
Play Group To XII Hindi & English Medium
MGH ROAD, JODHPUR- 342001 (Raj) 0291-2632070
SIR PRATAP ENGLISH PRIMARY EDUCATION BRAIN SCHOOL
(An English Medium School)
Class Prep to 8th

AYUSHI
BUILDCON PVT. LTD.

AYUSHI
BUILDERS & DEVELOPERS

221-222, Shyam Nagar, Pal Link Road, Jodhpur - 342 003 (Raj.)
Tel. : 0291-2710071 Mobile : 94141 27593, 93147 11416
E-mail : mdsharma74@live.in